



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]
No. 49]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1986/अग्रहायण 15, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1986/AGRAHAYANA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि और स्वाय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

सूचना

[का.आ. 4009 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सी. एम. भागवंदानी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नगरपालाविहार (दिल्ली) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं 5(82)/86-न्या.]

सक्षम प्राधिकारी
द्वारा एन. पौदार,

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 21st November, 1986

NOTICE

S.O. 4009.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules,

1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Chetan M. Bhagchandani, Advocate for appointment as a Notary to practise in Naraina Vihar (Delhi).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(82)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 24 नवम्बर 1986

का. आ. 4010.—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 475 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दण्ड न्यायालय और सेवा न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दण्ड न्यायालय और सेवा न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) संशोधन नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दण्ड न्यायालय और सेना न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1978 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

- (1) "यस सेना, नौ सेना या वायु सेना संबंधी विधि" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "सेना, नौ सेना, वायुसेना या तटरक्षक संबंधी विधि" शब्द रखे जाएंगे;
- (2) "सशस्त्र यस सेना, नौ सेना या वायु सेना, प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "सशस्त्र सेना, नौ सेना, वायु सेना या तटरक्षक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; और
- (3) "सेना न्यायालय" शब्दों के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "यथास्थिति सेना न्यायालय या तटरक्षक न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(क) खण्ड क में,—

- (i) उप खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) नौ सेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में, उस पोत या सौस्थावन या यूनिट का जिसका ऐसा व्यक्ति अंग है या जिससे वह संबन्ध है, कमान अधिकार अभिप्रेत है",

- (ii) उपखण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपखण्ड (iv) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) तटरक्षक संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में, उस तटरक्षक-पोत या स्थावन या यूनिट का जिसका वह अंग है या जिससे वह संबन्ध है, कमान अधिकार अभिप्रेत है"; और

- (ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित को खण्ड (ङ.) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) 'सशस्त्र तटरक्षक प्राधिकारी' से ऐसा महानिदेशक या महानिरोधक या उप महानिरोधक अभिप्रेत है, जिसके कमान के भीतर अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है,"।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में,—

- (i) "अभियुक्त का कमान अधिकार या, यथास्थिति, यस सेना, नौ सेना या वायु सेना का सशस्त्र प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; और
- (ii) "ऐसे अधिकार या प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; और
- (iii) "नियम 4 के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट शब्द अंक, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर "नियम 4 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/2/85-जुडिशियल सेल]
एन. पी. नवाणी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—यू.न. नियम, भारत के राजपत्र, तारीख 25-2-1978 में सं. फा. 488 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th November, 1986

S.O. 4010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Criminal Courts and

Court-Martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Criminal Courts and Court-Martial (Adjustment of Jurisdiction) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Criminal Courts and Court-Martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1978, (hereinafter referred to as "the said rules")—

(i) for the words "subject to military, naval or air force law" wherever they occur, the words "subject to military, naval, air force or coast guard law" shall be substituted;

(ii) for the words "competent military, naval or air force authority", wherever they occur, the words "competent military, naval, air force or coast guard authority" shall be substituted; and

(iii) for the word "court-martial", wherever it occurs, the words "court-martial or coast guard court, as the case may be" shall be substituted.

3. In rule 2 of the said rules,—(a) in clause (a)—

(i) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) in relation to a person subject to naval law, means the Commanding Officer of the ship or naval establishment or unit to which such person belongs or is attached,";

(ii) after sub-clause (iii) the following shall be inserted as sub-clause (iv), namely :—

"(iv) in relation to a person subject to the coast guard law, means the Commanding Officer of the coast guard ship or establishment or unit to which such person belongs or is attached,"; and

(b) after clause (d), the following shall be inserted as clause (e), namely :—

"(e) 'competent coast guard authority' means the Director General or Inspector General or Deputy Inspector General within whose command the accused person is serving."

4. In rule 5 of the said rules,—

(i) for the words "the commanding officer of the accused or the competent military, naval or air force authority, as the case may be", the word "such authority" shall be substituted; and

(ii) for the words "such officer or authority", the words "such authority" shall be substituted; and

(iii) for the words, figure, brackets and letters "referred to in clauses (a), (b), (c) and (d) of rule 4", the words and figure "under rule 4" shall be substituted.

[No. 2/2/85-Judl. Cell]

N. P. NAWANI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide No. SO 488 dated 9-2-1978 in the Gazette of India dated 25-2-78.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1986

शुद्धिपत्र

का. आ. 4011 :—सर्वसाधारण को सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, (राजस्व-विभाग) का दिनांक 31-3-1986 का अधिसूचना सं. 6638 को क्रम सं. (4) और (6) पर दिए गए कार्यक्रमों को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

के लिए	पढ़ा जाए
(4) अरावली की ऊतार भूमि को आर्थिक विकास परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(4) ऊतार भूमि का आर्थिक विकास परियोजना (उत्तर प्रदेश)
(6) अरावलीज को आर्थिक-विकास परियोजना	(6) अरावलीज में अधिक विकास परियोजना

[सं. 6893 (फा. सं. 203/43/86-आ. क. नि.-II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st September, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 4011. —It is hereby notified for general information that in Ministry of Finance, (Department of Revenue) Notification No. 6638 dated 31-3-1986, the programmes at Sl. No. (4) and (6) be read as follows :—

For	Read
(4) Usar Lands Eco-Development Project of Aravallis	(4) Usar Lands Eco-Development Project (U.P.)
(6) Eco-Development Project of Aravallis	(6) Eco-Development Project at Aravallis

[No. 6893 (F. No. 203/43/86-ITA.II)]

दिल्ली, 10 सितम्बर, 1986

आयकर

का. आ. 4012 :—इस कार्यालय की दिनांक 3-2-1984 की अधिसूचना सं. 5608 (फा. सं. 203/248/83-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जातकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारों, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनेस/एक/घो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रश्नों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणा, विहित प्राधिकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम अपना कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपराक्षित वार्षिक लेखों का तथा अपना परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलना-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारों को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन का समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का देर होने पर अर्चना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे”

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6905 (फा. सं. 203/133/86-आ. क. नि.-II)]

New Delhi, the 11th September, 1986

INCOME-TAX

S.O. 4012.—In continuation of this Office Notification No. 5608 (F. No. 203/248/83-ITA.II) dated 3-2-1984 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 Thirty Five|One|Two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association”, subject to the following conditions.—

- That the Bhaskaracharya Pratishthan, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Bhaskaracharya Pratishan, Pune.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1987.

[No. 6905 (F. No. 203/133/86-ITA-II)]

आयकर

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1986

का. भा. 4013.—इस कार्यालय की दि. 10-2-86 की अधि. सं. 6588 (फा. सं. 203/157/85-भा. क. नि.-II) के साथ पठित दिनांक 28-4-1984 को अधिसूचना सं. 5958 (फा. सं. 203/147/83-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि एल्कैमी रिसर्च सेंटर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"एल्कैमी रिसर्च सेंटर, क्रिसेंट हाऊस, पो. ऑ. बॉक्स नं. 180719, वालचन्द हीरा चन्द मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई-400038।"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6911 (फा. सं. 203/56/86-भा. क. नि.-II)]

INCOME-TAX

New Delhi, the 11th September, 1986

S.O. 4013.—In continuation of this Office Notification No. 5958 (F. No. 203/147/83-ITA. II) dated 28-4-1984 read with No. 6588 (F. No. 203/157/85-ITA. II) dated 10-2-1986 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association", subject to the following conditions :—

(i) That the Alchemie Research Centre will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Alchemie Research Centre, Crescent House, P. O. Box No. 180719, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay-400038.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 6911 (F. No. 203/56/86-ITA-II)]

का. भा. 4014.—सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि प्रोसेस इंजीनियरिंग डिजाइन डिवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कलकत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की

तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“प्रोसेस इंजीनियरिंग डिजाइन डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, 4-सी, नदी स्ट्रीट, कलकत्ता-700029।”

यह अधिसूचना 1-8-1986 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6908 (फा. सं. 203/90/86-आ. क. नि.-II)]

S.O. 4014.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions:—

- (i) That the Process Engineering, Design Development Institute, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Process Engineering Design Development Institute, 4-C, Nundy Street, Calcutta-700029.

This Notification is effective for a period from 1-8-86 to 31-3-88.

[No. 6908|F. No. 203/90/86-ITA-II]

का.आ. 4015.—इस कार्यालय की दिनांक 21-7-84 की अधिसूचना सं. 5903 (फा.सं. 203/91/84-आ.क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम

1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए “संगम” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

- (1) यह कि डॉ. रामाजिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आक्सीडेशनल हेल्थ सर्विसिज, पुणे-411002 अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त “संगम” अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त “संगम” अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त “संगम” केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“डॉ. रामाजिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आक्सीडेशनल हेल्थ सर्विसिज, 577 शुक्रवार पथ, पुणे-411002.”

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6909 (फा.सं. 203/134/86-आ.क.नि.-II)]

S.O. 4015.—In continuation of this Office Notification No. 5903 (F. No. 203/91/84-ITA-II) dated 21-7-84 It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions:—

- (i) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Dr. Ramzini Research Institute of Occupational Health Services, 577, Shukrawar Peth, Pune-411002.

This Notification is effective for a period from 1-4-86 to 31-3-88.

[No. 6909/F. No. 203/134/86-ITA-III]

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

का.आ. 4016.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (1) यह कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, अमरगढ़ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त "संगम" अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त "संगम" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त "संगम" केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, श्री के.जे. मेहता टी.बी. अस्पताल, अमरगढ़-364210."

यह अधिसूचना 14-5-86 से 31-1-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6912/फा.सं. 203/82/86-आ.क.नि.-II]

New Delhi, the 12th September, 1986

S.O. 4016.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the conditions :—

- (i) That the Tuberculosis Research Centre, Amargadh will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Tuberculosis Research Centre, Shri K. J. Mehta T.B. Hospital, Amargarh-364210, Saurashtra.

This Notification is effective for a period from 14-5-86 to 31-1-88.

[No. 6912/F. 203/82/86-ITA-III]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1986

का.आ. 4017.—इस कार्यालय की दिनांक 25-1-1982 की अधिसूचना सं. 4436 (फा.सं. 203/95/81-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैनीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (i) यह कि जैन विश्व भारती, राजस्थान, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

INSTITUTION

Jain Vishva Bharati, P.O. Ladnun, Rajasthan.

This Notification is effective for a period from 25-1-85 to 31-3-87.

[No. 6919/F. No. 203/95/86-ITA-II]

- (ii) यह कि उक्त "संस्थान" अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त "संस्थान" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"जैन विश्व भारती, पो. ऑ. लाडनन, राजस्थान"

यह अधिसूचना 25-1-85 से 31-3-87 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6919/फा. सं. 203/95/86-आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 15th September, 1986

S.O. 4017.—In continuation of this Office Notification No. 4436 (F. No. 203/95/81-ITA) dated 25-1-1982. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That Jain Vishva Bharati, Rajasthan will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said "Association" will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

का. आ. 4018.—इस कार्यालय की दिनांक 21-11-1984 की अधिसूचना सं. 6046 (फा. सं. 203/163/84-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (1) यह कि जय रामदास पटेल साइंटिफिक रिसर्च फाउण्डेशन, बम्बई-400001 अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"जय रामदास पटेल साइंटिफिक रिसर्च फाउण्डेशन, बम्बई-1"

यह अधिसूचना 1-7-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6920 (फा. सं. 203/146/86-आ. क. नि. II)]

S.O. 4018.—In continuation of this Office Notification No. 6046 (F. No. 203/163/84-ITA. II) dated 21-11-1984 It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay-400001. will maintain in a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said "Association" will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay.

This Notification is effective for a period from 1-7-1986 to 31-3-1988.

[No. 6920/F. No. 203/146/86-ITA-III]

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी, 1986

का. आ. 4019.—इस कार्यालय की दिनांक 29-5-84 की अधिसूचना सं. 5838 (फा. सं. 203/75/84-आ. क. नि.-II) के तिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (1) यह कि शिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउण्डेशन (इण्डिया), मद्रास अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए

तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राधान्य-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"शिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउण्डेशन (इण्डिया) नं. 2, II स्ट्रीट ओर्मस रोड, किल पौक, मद्रास-600010"।

यह अधिसूचना 1-4-86 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6921 (फा. सं. 203/142/86-आ. क. नि. II)]

New Delhi, the 17th September, 1986

S.O. 4019.—In continuation of this Office Notification No. 5838 (F. No. 203/75/84-ITA. II) dated 29-5-84. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Schizophrenia Research Foundation (India) Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Schizophrenia Research Foundation (India) No. 2, II Street Ormes Road, Kilpauk, Madras-600010.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1989.

[No. 6921/F. No. 203/142/86-ITA-III]

आयकर

का. आ. 4020.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,

नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैतिस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि टुवैन्टी फर्स्ट सेंचुरी इण्डिया सोसाइटी, चण्डीगढ़ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त "संस्थान" अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त "संस्थान" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"टुवैन्टी फर्स्ट सेंचुरी इण्डिया सोसाइटी, चण्डीगढ़।"

यह अधिसूचना 1-8-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6927 (फा. सं. 203/141/86-आ. क. नि. II)]

S.O. 4020.—It is hereby notified for general information, that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Twenty First Century India Society, Chandigarh will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet show-

ing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Twenty First Century India Society, Chandigarh.

This Notification is effective for a period from 1-8-86 to 31-3-1988.

[No. 6927 (F. No. 203/141/86-ITA-II)]

का० आ० 4021:—इस कार्यालय की दिनांक 23-4-84 की अधिसूचना सं० 5765 (फा० सं. 203/80/83-आ. क. नि.-II के सिलसिले में, सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतिस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है,

- (i) यह कि नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूजियम, कलकत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूजियम, 19-ए, गुरुसाय
रोड, कलकत्ता-700019”

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1989 तक की
अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 6924(फा. सं. 203/159/86-आ.क.नि. II)]

S.O. 4021.—In continuation of this Office Notification No. 5765 (F. No. 203/80/83-ITA. II) dated 23-4-84. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) That the National Council of Science Museum, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned, Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

National Council of Science Museum, 19-A, Gurusaday Road, Calcutta-700019.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1989.

[No. 6924 (F. No. 203/159/86-ITA-II)]

का. आ. 4022.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्—

- (i) यह कि बिरला इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च, ग्वालियर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पुष्कल लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिम-पत्तियां, देनदारियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“बिरला इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च, पो. आ. -रेजीडेंसी, ग्वालियर-474005”।

यह अधिसूचना 1-4-86 से 31-3-87 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6922(फा. सं. 203/103/86-आ.क.नि. II)]

S.O. 4022.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) That the Birla Institute of Medical Research, Gwalior will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Birla Institute of Medical Research, P. O. Residency, Gwalior-474005.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1987.

[F. No. 6922 (F. No. 203/103/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 22 मितम्बर, 1986

का. आ. 4023:—(इस कार्यालय की विनाश की अधिसूचना सं.) के

सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की

उपधारा (i) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है,

- (i) यह कि सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, चण्डीगढ़ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरण, विहित प्राधिकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारों को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, 2-ए, सेक्टर 19-ए, मध्या मार्ग चण्डीगढ़ 160019”.

यह अधिसूचना 1-8-1986 से 31-3-1988 तक को अधि के लिए प्रभाव है।

[सं. 6929(फा. सं. 203/143/86-प्रा. क. नि.-II)]

New Delhi, the 22nd September, 1986

S.O. 4023.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) That the Centre for Research in Rural & Industrial Development, Chandigarh, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of

their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

“Centre for Research in Rural & Industrial Development, 2-A, Sector 19-A, Madhya Marg, Chandigarh-160019”.

This Notification is effective for a period from 1-8-1986 to 31-3-1988.

[No. 6929 (F. No. 203/143/86-ITA-II)]

का.प्रा. 4024.—इन कार्यालय को दिनांक 14-9-84 को अधिसूचना सं. 5979 (फा.सं. 203/81/83-प्रा.क. नि.-2) के सिलसिले में, सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एवद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 को उपधारा (1) के खंड (2) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए “कॉलिज” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि राम नारायण रुईया कॉलिज, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त कॉलिज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरण, विहित प्राधिकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त “कॉलिज” अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारों को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त “कॉलिज” केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“राम नारायण रुईया कॉलेज, मतुंग, बम्बई-400019

यह अधिसूचना 1-9-1986 से 31-3-1989 तक का अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6932 (फा.सं. 203/201/86-आ.क.नि.-2)]

S.O. 4024.—In continuation of this Office Notification No. 5979 (F. No. 203/81/83-ITA. II) dated 14-9-84. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “College” subject to the following conditions :—

- (i) That the Ram Narain Ruia College, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said College will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Ram Narain Ruia, College, Matunga, Bombay-400019.
This Notification is effective for a period from 1-9-1986 to 31-3-1989.

[No. 6932 (F. No. 203/201/86-ITA-II)]

का.मा. 4025:—इस कार्यालय की दिनांक 7-2-84 की अधिसूचना सं. 5702 (फा.सं. 203/16/84-आ.क.नि.-2) के सिलसिले, में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैसा/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है।

- (1) यह कि विश्व भारती, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत

करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (3) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपना कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपराक्षित वार्षिक लेखों का तथा अपना परिसंपत्तियां, देनदारियां दशति हुए तुलन-पत्र का एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक-एक प्रति संबंधित आयकर अभ्युक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त विश्वविद्यालय केंद्राय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन का समाप्ति से तान माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रायश्चित्त रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235”

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6930 (फा.सं. 203/200/86-आ.क.नि.-2)]

S.O. 4025.—In continuation of this Office Notification No. 5702 (F. No. 203/16/84-ITA. II) dated 7-2-1984. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “University” subject to the following conditions :—

- (i) That the Visva Bharati, Shantiniketan, West Bengal, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said University will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said University will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said University will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

“Visva Bharati, Shantiniketan, West Bengal-731235”.
This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1989.

[No. 6930 (F. No. 203/200/86-ITA-II)]

का.आ. 4026:—इस कार्यालय की दिनांक 23-5-85 की अधिसूचना सं. 6231 (फा.सं. 203/57/85-आ.क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 का धारा 35 को उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोस/एक/तान) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(i) यह कि मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, जम्मू अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरण, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपराक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां, दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त "संस्थान" केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार को देर होने पर प्रार्थना-पत्र रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, बी. सी. रोड, जम्मू-180001"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6928 (फा.सं. 203/101/86-अ.ई.०००-ए०-II)]

S.O. 4026.—In continuation of this Office Notification No. 6231 (F. No. 203/57/85-ITA. II) dated 23-5-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five) One Three of the Income-tax Act, 1961 read with Rule-6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Model Institute of Education & Research, Jammu will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Model Institute of Education & Research, B. C. Road, Jammu-180001".

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 6928 (F. No. 203/101/86-ITA-II)]

का. आ. 4027:—इस कार्यालय की दिनांक 31-3-85 की अधिसूचना सं. 6354 (फा. सं. 203/166/84-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 को उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसायटी, सटूर, (महाराष्ट्र) अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरण, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपराक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसायटी, लतूर, महाराष्ट्र-413 512"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक का अवधि के लिए प्रभावी है।

[संख्या 6931 (फ. सं. 253/145/86-आ. क. नि.-II)]

S.O. 4027.—In continuation of this Office Notification No. 6354 (F. No. 203/166/84-ITA, II) dated 31-7-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Vivekanand Medical Research Society, Latur, (Maharashtra) will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance, before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Vivekanand Medical Research Society, Latur, Maharashtra-413512".

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 6931 (F. No. 203/145/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1986

का. आ. 4028 :—हम कार्यालय की दिनांक 11-10-84 की अधिसूचना सं. 6019 (फा. सं. 203/88/83-आ. क. नि.-II) के मिलमिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की

धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अर्थात् निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (i) यह कि सेंट्रल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, नागपुर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपने कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संघटित वार्षिक लेखों की तथा अपने परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सेंट्रल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, 28/2, बजाज नगर, नागपुर-440 010"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 30-6-1987 तक का अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6933 (फा. सं. 203/91/86-आ. क. नि.-II)]

वाई. के. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 1986

S.O. 4028.—In continuation of this Office Notification No. 6019 (F. No. 203/88/83-ITA, II) dated 11-10-84, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Central India Institute of Medical Sciences, Nagpur, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in

such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Central India Institute of Medical Sciences, 88/2, Bajaj Nagar, Nagpur-440010.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 30-6-1987.

[No. 6933 (F. No. 203/91/86-ITA-II)]
Y. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4029:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मास इक्कीस करोड़ पच्चास लाख पचाह हजार छः सौ रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों "9.75 तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऋण, 1999" के स्वरूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 47/86-स्टाम्प-फा. सं. 33/58/86-वि. क.]

New Delhi, the 14th November, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 4029.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes "9.75 per cent. Tamil Nadu Electricity Board Loan 1999" to the value of rupees twenty one crores twenty five lakhs eleven thousand and six hundred only to be issued by the Tamilnadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. No. 47/86-Stamp F. No. 33/58/86-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4030:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मास पन्द्रह करोड़ पचाह लाख पच्चास हजार छः सौ रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों 9.75 तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऋण 1998 (दूसरी श्रृंखला) के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 46/86-स्टाम्प/फा. सं. 33/59/86-वि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 4030.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes, "9.75 per cent. Tamil Nadu Electricity Board Loan, 1998 (2nd Series) to the value of rupees Fifteen crores eleven lakh and twenty five thousand and six hundred only to be issued by the Tamilnadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. 46/86-Stamp/F. No. 33/59/86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1986

(घायकर)

का. आ. 4031:—घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ठ की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित ऋणपत्रों को निविष्ट करती है, अर्थात् :—

मे. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी किए गए 7 वर्षीय '14 प्रतिशत भारशित विमोक्ष्य असंपरिवर्तनीय बंधपत्र।'

[फा. सं. 178/81/86-भा. क. (वि.-1)]

रोशन साहाय, अवर सचिव

New Delhi, the 17th October, 1986

INCOME-TAX.

S.O. 4031.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 80-L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following debentures for the purposes of the said clause, namely :—

7-Lear "14 per cent secured Redeemable Non-convertible Bonds" issued by M/s. Neyveli Lignite Corporation Limited.

[F. No. 178/81/86-IT(AI)]
ROSHAN SAHAY, Under Secy.

(व्यवसायिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

का. भा. 4032.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी. एम. तिरुथानी को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-6-1986 को समाप्त हो गयी है 1-7-1986 से प्रारम्भ होकर 31-8-1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 2-23/86-आर. आर. बी.]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 4032.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby re-appoints Shri B. M. Tiruthani whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of Section 11 had expired on 30-6-86 as the Chairman of Shahdol Kshetriya Gramin Bank, Shahdol (M.P.) for a further period commencing from 1-7-86 and ending with 31-8-86.

[No. F. 2-23/86-RRB]

का. भा. 4033.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस. सी. मेहता को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (मध्य प्रदेश) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-6-1985 को समाप्त हो गयी है, 1-7-85 से प्रारम्भ होकर 28-8-1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 2-23/86-आर. आर. बी.]

S.O. 4033.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby re-appoints Shri S. C. Mehta whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 30-6-85 as the Chairman of Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank, Jhabua (M.P.) for a further period commencing from 1-7-85 and ending with 28-8-86.

[No. F. 2-26/86-RRB]

का. भा. 4034.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री कालूराम जैन को झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (मध्य प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-8-1986 से प्रारम्भ होकर 31-8-1989 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री कालूराम जैन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-26/86-आर. आर. बी.]

S.O. 4034.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Kaluram Jain, Chairman, Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank, Jhabua (M.P.) and specifies the period com-

mencing on the 29-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri Kaluram Jain shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-26/86-RRB]

का. भा. 4035.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन. सी. शुकला को शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14-8-1986 से प्रारम्भ होकर 31-8-1989 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन. सी. शुकला अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-23/86-आर. आर. बी.]

S.O. 4035.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri N. C. Shukla, Chairman, Shahdol Kshetriya Gramin Bank, Shahdol, Madhya Pradesh and specifies the period commencing on the 14-8-86 and ending with 31-8-89 as the period for which the said Shri N. C. Shukla shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-23/86-RRB]

का. भा. 4036.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री पी. सी. यादव को भागीरथ ग्रामीण बैंक, सतापुर (उ.प्र.) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-7-1986 से प्रारम्भ होकर 31-7-1989 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री पी. सी. यादव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एक. 2-8/86-आर. आर. बी.]

S.O. 4036.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri P. C. Yadav as the Chairman of Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.) and specifies the period commencing on the 31-7-86 and ending with the 31-7-89 as the period for which the said Shri P. C. Yadav shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-8/86-RRB]

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1986

का. भा. 4037.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सुधाकर शेट्टी को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 31-8-1986 को समाप्त हो गई है 1-9-86 से प्रारम्भ होकर 4-9-1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 2-25/86-आर. आर. बी.]

New Delhi, the 10th November, 1986

S.O. 4037.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby reappoints Shri H. Sudhakar Shetty, whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31-8-86 as the Chairman of Chitradurga Gramin Bank, Chitradurga (Karnataka) for a further period commencing from 1-9-86 and ending with 4-9-86.

[No. F. 2-25/86-RRB]

का. आ. 4038.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के धारा 11 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय सरकार एतद्वारा श्री डी. वी. राव को चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5-9-1986 से प्रारम्भ होकर 30-9-1989 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी. वी. राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-25/86-आर. आर. बी.]

S.O. 4038.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri D. V. Rao, Chairman, Chitradurga Gramin Bank, Chitradurga (Karnataka) and specifies the period commencing on the 5-9-86 and ending with 30-9-89 as the period for which the said Shri D. V. Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 25/86-RRB]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1986

का. आ. 4039.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय सरकार श्री बी. रमेश को जिनके द्वारा 11 की उपधारा (1) के तहत मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का तन वष को पहल अवधि 28-2-86 को समाप्त हो गई है, 1-3-86 से प्रारम्भ होकर 31-7-86 को समाप्त होने वाले अवधि के लिये उक्त बैंक क पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 2-7/86-आर. आर. बी.]

New Delhi, the 17th November, 1986

S.O. 4039.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby reappoints Shri B. Ramesh whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 28-2-86 as the Chairman of Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga for a further period commencing from 1-3-86 and ending with 31-7-86.

[No. F. 2-7/86-RRB]

का. आ. 4040.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय सरकार एतद्वारा श्री आर. लक्ष्मण राव को मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-7/86-आर. आर. बी.]

च. ब. मोरचन्दानी, निदेशक

S.O. 4040.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R. Laxman Rao as the Chairman of the Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga and specifies the period commencing on the 1-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F/2-7/86-RRB]

C. W. MIRCHANDANI, Director

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

गुडिपत्र

का. आ. 4041.—दिनांक 3 अक्टूबर, 1986 की अधिसूचना सं. 6951/86 (फा. सं. 261/26/86-अ. क. न्या.) के पैरा 3 में 1157G/86-3

जायू होने का तारीख 1-10-1986 के स्थान पर 16-10-1986 पढ़ा जायें।

[सं. 6989/86 (फा. सं. 261/28/86-अ. क. न्या.)]

ए. के. गर्ग, अवसर मन्त्रि

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 31st October, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 4041.—In para 3 of notification No. 6951/86 (F. No. 261/26/86-ITJ) dated 3rd October, 1986 the effective date of 1-10-86 may be read as 16-10-86.

[No. 6889/86 (F. No. 261/28/86-ITJ)]

A. K. GARG, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1986)

का० आ० 4042.—भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई को संलग्न सूची के अनुसार 71,070/- रु० (£ 4626) के 3 नव मेल ओपनिंग मशीन एटैचमेंट के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट नं. पी/जे/3071395/एन/एम एन/90/एच/एम एल. एस, दिनांक 8-3-84 दिया गया था जिसकी वैधता अवधि उसे जारी करने की तारीख से 6 मास की थी। श्रव पार्टी ने उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिए इन आचार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। पार्टी ने आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी सीमाशुल्क सदन से पंजीकृत नहीं किया गया है और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। सीमा शुल्क निकासी परमिट की शेष राशि 71,070/- रु. थी। शपथपत्र में इन आचार की घोषणा भी जोड़ी गई है कि उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट यदि बाध में मिल जाता है तो उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा। अखोस्ताखरी इन बात से संतुष्ट होने पर कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है यह निदेश देने हैं कि आवेदक को अनुलिपि सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाए। आयात (नियंत्रण) प्रादेश, 1955 की धारा (9) की उध धारा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द करता हूँ।

[फा. सं. 2/222/83-84/एम. एल. एस./454]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 24th November, 1986

S.O. 4042.—State Bank of India, Bombay were granted a CCP No. P/J/3071395/N/MN/90/H/MLS dated 8-3-84 for import of 3 Nos. Mail Opening Machines attachments as per list attached valued at Rs. 71,070 (£ 4626) with a validity of 6 months from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate CCP of the aforesaid CCP on the ground that the CCP has been lost. The party has furnished necessary affidavit according to which the

aforesaid CCP was not registered with any customs house and was not utilised at all and the balance against the CCP is Rs. 71,070. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said CCP is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. On being satisfied that the original CCP has been lost, the undersigned directed that a duplicate CCP should be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (d) of Clause 9 of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the original CCP.

[F. No. 2/222/83-84/MLS/454]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller
of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Exports

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1986

का.घा. 4043:— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजराज राज्य में रामोने जी.सा. प्रैस रिफायनरी उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोजन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन के प्रयोजन के लिये एतद् पाट्टा कनसुमि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का आदेश आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उप भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशय सन्नम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोजन, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वाडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

रामोने जी.सी. एस. से रिफायनरी उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य: गुजरात, जिला: अहमदाबाद, तालुका: दम कोई

गाँव:	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर
1	2	3	4	5
मेहमदपुर	63	0	19	50
	64	0	26	40
	72	0	22	50
	71	0	09	00
	70	0	02	30
	69	0	14	40
	82	0	20	40
	85	0	06	00
	89	0	10	80
	87	0	08	40
	88	0	10	80
	94	0	16	80
	108	0	15	60
	105	0	00	30

1	2	3	4	5
	107	0	01	80
	109	0	16	80
	110	0	10	50
	113	0	12	00
	114	0	14	55
	86	0	00	25

[सं. जी. 12016/203/86-ओएनजी-सी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 19th November, 1986

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol, GCS to Reliance Industries

State : Gujarat	District : Ahmedabad	Taluka	Dascroi	
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Memadpur	63	0	19	50
	64	0	26	40
	72	0	22	50
	71	0	09	00
	70	0	02	30
	69	0	14	40
	82	0	20	40
	85	0	06	00
	89	0	10	80
	87	0	08	40
	88	0	10	80
	94	0	16	80
	106	0	15	60
	105	0	00	30
	107	0	01	80
	109	0	16	80
	110	0	10	50
113	0	12	00	
114	0	14	55	
86	0	00	25	

का.मा. 4044:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रानोल जी.सी. प्रत से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्विषयक अनुसूच में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किस्म: विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी.सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात, जिला: अहमदाबाद, तालुका: दसक्रोई

ग्राम	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर	सेन्टीयर
बीबीपुर	11	0	04	48
	10	0	00	60
	15	0	00	60
	16	0	10	80
	17	0	17	70
	34	0	06	00
	35	0	07	20
	36	0	06	60
	37	0	07	20
	38	0	01	20
	41	0	06	60
	48	0	27	60
	47	0	16	60
	51	0	03	90

[सं. ओ-12016/204/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rumol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries

State: Gujarat District: Ahmedabad Taluka: Dasroi

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Bibipur	11	0	04	48
	10	0	00	60
	15	0	00	60
	16	0	10	80
	17	0	17	70
	34	0	06	00
	35	0	07	20
	36	0	06	60
	37	0	07	20
	38	0	01	20
	41	0	06	60
	48	0	27	60
	47	0	16	60
	51	0	03	90

[No. O-12016/204/86-ONG-D-4]

का.मा. 4045:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रानोल जी.सी. प्रत से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्विषयक अनुसूच में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची				
रामोल जी.सी. एस. से रिलायंस उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए				
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दस क्रोई				
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर
भुवालडी	516	0	24	00
	517	0	09	60
	526	0	36	00
	525	0	10	50
	537	0	09	60
	538	0	04	80
	539	0	00	30
	540	0	06	00
	541	0	04	50
	573	0	19	20
	556	0	12	00
	572	0	01	80
	557	0	09	60
	565	0	12	00
	कार्ट ट्रैक	0	03	00
	713	0	34	80

[सं. O-12016/202/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 4045.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rumol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dasecroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhuvaldi	516	0	24	00
	517	0	09	60
	526	0	10	00
	525	0	36	50
	537	0	09	60
	538	0	04	80
	539	0	00	30

1	2	3	4	5
	540	0	06	00
	541	0	04	50
	573	0	19	20
	556	0	12	00
	572	0	01	80
	557	0	09	60
	565	0	12	00
	Cart track	0	03	00
	713	0	34	80

[No. O-12016/202/86-ONG-D4]

का.प्रा. 4046.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी.सी. एस. से रिलायंस उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाने चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदप्राप्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जं.सी.एस. से रिलायंस उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : दसक्रोई			
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्ट	यार्ड
गेरत नगर (गेरतनगर)	44	0	04	80	
	45	0	18	00	
	47	0	05	40	
	48	0	06	15	
	कार्ट ट्रैक	0	04	10	
	123	0	16	20	
	122	0	00	60	
	125	0	07	20	
	126	0	09	60	
	121	0	15	60	
	120	0	01	20	
	127	0	01	50	
	119	0	19	20	
	118	0	00	30	

[सं. O-12016/201/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 4046.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rumol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe Line From Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat District : Amedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Geratnagar	44	0	04	80
	45	0	18	00
	47	0	05	40
	48	0	06	15
	Cart track	0	04	10
	123	0	16	20
	122	0	00	60
	125	0	07	20
	126	0	09	60
	121	0	15	60
	120	0	01	20
	127	0	01	50
	119	0	19	20
	118	0	00	30

[No. O-12016/201/86-ONG D4]

का. भा. 4047.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदापवाद अनुसूच. में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणख्य एतद्वारा घोषित किया है बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नोबे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : दसक्रोई		
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	अर.	सेण्टीयर
रामोल	141/3	0	18	00
	140	0	00	30

[स. O-12016/200/86-ओ. एन. जी.-बी.-4]

S.O. 4047.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ramol	141/3	0	18	00
	140	0	00	30

[No. O-12016/200/86-ONG-D4]

का. भा. 4048.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोला ज. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदापवाद अनुसूच. में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणख्य एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नोबे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह बहु चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कठवाडा	133	0	19	50
	134	0	32	30
	123	0	13	50
	122	0	19	50
	121	0	30	00
	219	0	25	50
	221	0	09	00
	223	0	09	00
	228	0	01	50
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	225	0	27	00
	227	0	21	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	328	0	12	00
	327	0	24	00
	321	0	06	00
	324	0	32	25
	439	0	15	00
	436	0	12	00
	434	0	20	25
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	465	0	27	00
	467	0	15	75
	468	0	00	00
	563	0	10	50
	569	?	09	00
	568	0	09	75
	567	0	10	50
	592	0	10	50
	595	0	00	60
	224	0	00	60

[सं. O-12016/198/86-मो. एन. जी. सी. 4]

S.O. 4048.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the

Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Das
croi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kathavada	133	0	19	50
	134	0	32	30
	123	0	13	50
	122	0	19	50
	121	0	30	00
	219	0	25	50
	221	0	09	00
	223	0	09	00
	228	0	01	50
	Cart Track	0	01	20
	225	0	27	00
	227	0	21	00
	Cart Track	0	01	50
	328	0	12	00
	327	0	24	00
	321	0	06	00
	324	0	32	25
	439	0	15	00
	436	0	12	00
	434	0	20	25
	Cart Track	0	01	50
	465	0	27	00
	467	0	15	75
	468	0	00	00
	563	0	10	50
	569	0	09	00
	568	0	09	75
	567	0	10	50
	592	0	10	50
	295	0	00	60
	224	0	00	60

[No. O-12016/198/86-ONG D4]

का. भा. सं. 4048.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सौकरित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी. जी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनडाब्लू मनुष्यों में बजिन भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बताने कि उक्त भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस भूमि के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिए आशय सख्त प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रदान, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा धारण करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	प्रार.	सेन्टीमीटर
सिंगरवा	133/2	0	06	00
	127	0	42	30
	124/3	0	14	40
	124/2	0	10	50
	124/1	0	06	60
	123	0	06	15
	101/1	0	06	00
	102	0	30	60
	98	0	12	00
	97	0	12	60

[सं. 0-12016/199/86-ओ. एन. जी. बी. 4]

S.O. 4049.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Valledara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe Line From Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Das-croi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Singarva	133/2	0	06	00
	127	0	42	30
	124/3	0	14	40
	124/2	0	10	50
	124/1	0	06	60
	123	0	06	15
	101/1	0	06	00
	102	0	30	60
	98	0	12	00
	97	0	12	06

[No. O-12016/199/86-ONG D4]

का. प्रा. सं. 4050.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपान्न अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बनवें कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के लोके पाइप-लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोवा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा धारण करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : सीटो

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	प्रार.	सेन्टीमीटर
नरोडा	670	0	00	30
	669	0	16	80
	668	0	08	40
	672	0	02	70
	667	0	07	50
	663	0	11	85
	684	0	16	80
	661	0	13	50
	680	0	12	00
	651	0	09	60
	650/2	0	00	80
	650/1	0	08	80
	627	0	13	50
	626	0	11	70
	625	0	08	40
	528/3	0	13	20
	528/1	0	11	70

[सं. O-12016/197/86-ओ. एन. जी. —बी. 4]

प. ० के. ० राजगोपालन, डी. स्क अधिकारी

S.O. 4050.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat	District : Ahmedabad	Taluka : City		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Naroda	670	0	00	30
	669	0	16	80
	668	0	08	40
	672	0	02	70
	667	0	07	50
	663	0	11	85
	664	0	16	80
	661	0	13	50
	660	0	12	00
	651	0	09	60
	650/2	0	00	80
	650/1	0	08	80
	627	0	13	50
	626	0	11	70
	625	0	08	40
	529/3	0	13	20
	529/1	0	11	70

[No. O-12016/197/86-ONG D4]

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

का. अ. 4051 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. दिल्ली नगर कला आयोग,
लोक नायक भवन,
पृथ्वीराज लेन, नई दिल्ली।

[संख्या ई-11017/9/85-हिन्दी]

वन श्याम, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st November, 1986

S.O. 4051.—In pursuance of Sub-rule 4 of Rule 10 of the Official language (Use for Official purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office under the Ministry of Urban Development whereof more than 80 per cent Staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Delhi Urban Art Commission,
Lok Nayak Bhawan,
Prihvi Raj Lane,
New Delhi.

[No. E-11017/9/85-Hindi]

GHANSHYAM, Dy. Director (Official Language)

दूरसंचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

का. अ. 4052.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने राजपिपला टेलीफोन केन्द्र, गुजरात सकल में दिनांक 08-12-86 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-21/86-पी एच बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 20th November, 1986

S.O. 4052.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of India Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 8-12-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Rajpipla Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-21/86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर 1986

का. अ. 4053.—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा कर्नाटक सरकार के परामर्श से डा. एस. टी. नागालिंगासेटी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, बंगलूर की इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उप-खण्डों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय, की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का. अ. 133 में दिये निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3(1) (क) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के प्रथमतः कम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"12. डा. एस. टी. नागालिंगासेटी, निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, बंगलूर"

[संख्या बी. 11013/7/86-एम.ई. (पी.)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 19th October, 1986

S.O. 4053.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Karnataka have nominated Dr. S. T. Nagalinga Setty, Director of Medical Education.

Bangalore, to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the revisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under section 3(1)(a), for serial number 12 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"12. Dr. S. T. Nagalinga Setty,
Director of Medical Education,
Bangalore."

[No. V. 11013/17/86-ME(P)]

का. डा. 4054.—डा. डी. सी. चौधरी, प्रधानाचार्य, गवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, 1 मार्च, 1986 से सेवा निवृत्त हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अध्या के बाद जिसे उक्त अधिनियम कहा गया है। धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा असम सरकार के परामर्श से डा. एन. जयन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, असम की डा. डी. सी. चौधरी के स्थान पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अध्या, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय, की 9 जनवरी, 1960 की अधिवृत्ता संख्या का. डा. 138 में दिये निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिवृत्ता में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

"(9) डा. एन. जयन, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, असम"

[संख्या बी. 11013/13/86-एम. ई. (पी.)]

S.O. 4054.—Whereas, Dr. D. C. Choudhury, Principal, Gauhati Medical College, Gauhati, has retired from the service with effect from 1st March, 1986;

And whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and in consultation with the Government of Assam have nominated Dr. N. Zaman, Director of Medical Education, Assam, to be the member of the Medical Council of India vice Dr. D. C. Choudhury.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health, No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3", for serial number 9 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"9. Dr. N. Zaman, the Director of Medical Education, Assam".

[No. V. 11013/13/86-ME(P)]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1986

का. डा. 4055.—केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) धारा 14 की उप-धारा (1) 1157 G/86—4

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के बाद यह निदेश देती है कि इस अधिवृत्ता के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कोनम्बो विश्वविद्यालय, श्रीलंका द्वारा प्रदत्त "बैचुलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बैचुलर ऑफ सर्जरी" चिकित्सा अध्या उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त चिकित्सा अध्या होगी।

[संख्या बी. 11016/6/84—एम. ई. (पी.)]

शिव दयाल, उप सचिव

New Delhi, the 19th November, 1986

S.O. 4055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the medical qualification 'Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery' granted by the Colombo University, Sri Lanka, shall be recognised medical qualification from the date of issue of this notification in the Official Gazette, for the purposes of the said Act.

[No. V. 11016/6/84-ME(P)]
SHIV DAYAL, Dy. Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

का. डा. 4056.—केन्द्रीय सरकार, डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) नियम, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत परन्तु के माध्यम से डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 5 ए की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा श्री पी. सोलोमन अब्राव को श्री के. जी. भगत जिनका देहात 14 जुलाई, 1986 को हुआ था, के स्थान पर कोचीन गोदो श्रमिक मंडल का सदस्य नियुक्त करती है, तथा यह निदेश देती है कि भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, जल भूतल परिवहन विभाग की अधिवृत्ता सं. का. डा. 786 (ए), दिनांक 25 अक्टूबर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएँ, अर्थात् :—

उक्त अधिवृत्ता में मद्र सं. 2 के सामने "डॉक वर्कर्स और नौकरान कम्पनियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के नीचे "श्री के. जी. भगत" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री पी. सोलोमन अब्राव" प्रविष्टि रखी जाए।

[काइल सं. एन डी एक्स/6/85—यू. एन. (एन)]

सुदेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 21st November, 1986

S.O. 4056.—In pursuance of sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri P. Solomon Abrao as a member of the Cochin Dock Labour Board vice Shri K. G. Bhagat, who expired on 14th July, 1986 and direct that the following amendments shall be made in the notification of Government of India in the Ministry of Transport, Department of Surface Transport (Transport Wing) No. S.O. 786(E), dated the 25th October, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the employers of Dock Workers and Shipping Companies", against item 2, for the entry "Shri K. G. Bhagat", the entry "Shri P. Solomon Abrao" shall be substituted.

[F. No. LDX/6/85-US(L)]
SUDESH KUMAR, Under Secy.

अव मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

का. आ. 4057 :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि फासफेट खनन उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[एस - 11017/4/85 - डी - I (ए)]

नन्द लाल, अव सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st November, 1986

S.O. 4057.—Whereas the Central Government is satisfied that the Public interest requires that the Phosphate Mining Industry, which is covered by entry 23 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/4/85-D. I(A)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

का. आ. 4058 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के पैरा 28 के अनुसरण में यह निदेश देती है कि 31 मार्च, 1986 को कुटुम्ब पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों और उसके बाद के कुटुम्ब पेंशन भोगियों को अनु-पूरक वृद्धियां नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर अप्रैल, 1986 के पहले दिन से दी जाएगी :-

- (1) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये 20 रुपये प्रति माह की प्रति मास तक पेंशन ले रहे थे वृद्धि।
- (2) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये 30 रुपये प्रति माह से अधिक और 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि तक पेंशन ले रहे थे।
- (3) ऐसे पेंशन भोगी जो 200 रुपये 40 रुपये प्रति माह प्रति माह से अधिक पेंशन ले रहे थे की वृद्धि।

2. अनुपूरक वृद्धि की दरें ऐसे कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के पैरा 28 (1) के निबन्धनों के अनुसार संदेय होगी।

3. उपरोक्त अनुपूरक वृद्धि पहले की अधिसूचना संख्या का. आ. 1351, ता. 16 फरवरी, 1983; का. आ. 1611, ता. 5-3-1983; का. आ. 2609, ता. 21-7-1984 और का. आ. 1607 तारीख 28-3-1985 द्वारा मंजूर की गई अनुपूरक वृद्धियों के अतिरिक्त होगी।

[संख्या आर - 11025/7/84 - एस०एस०-4]

ए. के. भट्टारай अव सचिव

New Delhi, the 21st November, 1986

S.O. 4058.—In pursuance of the paragraph 28A of the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the Central Government hereby directs that the Family Pensioners as on 31st March, 1986 and thereafter shall be granted supplementary additions at the rates specified below with effect from the 1st day of April, 1986 :—

(i) Pensioners who were drawing pension upto Rs. 100/- per month	An increase of Rs. 20/- per month.
(ii) Pensioners who were drawing pension above Rs. 100/- per month upto Rs. 200/- per month	An increase of Rs. 30/- per month.
(iii) Pensioners who were drawing pension above Rs. 200/- per month	An increase of Rs. 40/- per month.

2. The rate of supplementary additions will be related to the Family Pensioners would be payable to in terms of para 28(1) of the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

3. The above supplementary additions will be in addition to the supplementary additions sanctioned earlier vide S.O. 1351 dated 16-2-1983; S.O. 1611, dated 5-3-1983; S.O. 2609 dated 21-7-1984 and S.O. 1607, dated 28-3-1985.

[F. No. R-11025/7/84-SS-IV]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

का. आ. 4059.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :-

1. मैसर्स मेटल एंड प्लास्टिक कॉम्पोनेन्ट्स, इन्डियन जेड 8/4, (द्वितीय मंजिल) कॉर्पोरेट नगर, इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-15
2. मैसर्स अजमेर एंड कम्पनी, 6 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5
3. मैसर्स राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-20
4. मैसर्स पर्स डिजिटल सिस्टम्स, ए-100 डी० डी० ए० सेडस, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 नई दिल्ली-20

5. मैसर्स के० एन० के० कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ई-42/4 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-20

6. जैनको इन्डस्ट्री कैमोकलस ई-43 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-20

7. मैसर्स दी पोलिशो ग्रुप, हैरलड हाऊस, 5ए बहादुरशा जंकर मार्ग, नई दिल्ली-2

3. रीता कपूर इंडस्ट्राइज (प्रा.) लि., 3ई/2 अन्डेगाना एम्प्लेयमेंट, नई दिल्ली-55

9. मैसर्स शिखर मर्चेन्डाईज कार्पोरेशन, बी-2, कम्पिटेंट हाऊस, एन-14, मिडिल सर्कल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

10. मैसर्स यूआईटीडी फर्मा, इन्टरनेशनल लिमिटेड 502, हेनहुट टावर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 और इसका 66 जोती नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 तथा 107-110 सेक्टर 17बी चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय तथा गांव जोनियावास जिन्ना महेश्वर गढ़ (हरियाणा) स्थित फैक्ट्री।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस - 35019 (174)/86 एस एस - 2]

New Delhi, the 21st November, 1986

S.O. 4059.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Metal and Plastic Components, (WZ-8/4, (2nd Floor), Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15.
2. M/s. Ajmer and Co., 6, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-5.
3. M/s. National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NSIC) PDTC (Campus, Okhla Industrial Area, New Delhi-20.
4. M/s. Pearl Digital Systems, A-100, D.D.A. Sheds, Okhla Industrial Area, Phase, II, New Delhi-20.
5. M/s. KNK Components (Pvt.) Ltd., E-42/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20.
6. M/s. Jainco Industry Chemicals, E-43, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20.
7. M/s. The Policy Group, Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-2.
8. M/s. Kapoor Enterprises (West), 3E/2, Jhandewalan, Extension, New Delhi-55.
9. M/s. Shikhar Merchandise Corporation B-2, Competent House, F-14, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-1.
10. M/s. United Pharma International Ltd., 502, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-19 including its office at 66 Joyte Nehru Place, New Delhi-19 and 107-110, Sector-17-B, Chandigarh and factory at village Joniawas, District Mohindergarh (Haryana).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act, to the abovementioned establishments.

[S. 35019(174)/86-SS-II]

का. आ. 4060.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स स्टेट बैंक स्टाफ कन्ज्युमर्स कोप्रेटिव स्टोर्स लिमिटेड, केवर आफ स्टेट बैंक आफ इंडिया, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-23

2. मैसर्स मैक्रोफिल इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड, 9, वालेस स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1

3. मैसर्स लिबर्टी ऑफसेट, 428 शाह एंड नाहर इंडस्ट्रियल स्टेट, लोअर मेरल, बम्बई-13

4. मैसर्स रोसो इम्पेक्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, 45-ए विंग, मिशन टावर, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई-21,

5. मैसर्स नैकस एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड, प्रथम मंजिल, जोजो हाऊस, 17 रेवलाइन स्ट्रीट, बम्बई-1 और इसका ब्लाक नं. 4 ड्राइव इन थियटर बांद्रा (पूर्व) बम्बई-51 स्थित स्टूडियो।

6. मैसर्स त्रिनाशा सर्विसिज, 204 चन्दन चैम्बर्स, 138 मोदी स्ट्रीट फोर्ट मार्केट बम्बई-1 और इसकी जवाहर कोप्रेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट प्लॉट नं. 210/211, कमाथ, पनवल-6 स्थित फैक्ट्री।

7. मैसर्स एमिरेट्स मर्कस चैम्बरस-5 रुम नं. 221 द्वितीय मंजिल, नारीमन प्वाइन्ट बम्बई-21 और इसका कनरा नं. 1507 कनिष्क हाउस, 19 अशोक रोड, नई दिल्ली-1 स्थित कार्यालय।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस - 35018 (9)/86 एसएस-2]

S.O. 4060.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. State Bank's Staff Consumers' Co-operative Store Limited, C/o State Bank of India, Mumbai Samachar Marg, Mumbai-23.
2. M/s. Macrofil Investments Limited, 9, Wallace Street, Fort, Bombay-1.
3. M/s. Liberty Offset, 428, Shah and Nahar Industrial Estate, Sitaram Jadhav Marg, Lower Parel, Bombay-13.

4. M/s. Roffe Impex International Private Limited, 45-A Wing Mittal Tower Nariman Point, Bombay-21.
5. M/s. Nexus Advertising Private Limited, 1st Floor, Jiji House, 17, Raveline Street, Bombay-1 and its Studio at Block No. 4, Drive-in Theatre Bandra (E) Bombay-51.
6. M/s. Vinodha Services 204, Chandah Chambers, 138, Modi Street, Fort Market, Bombay-1, including its factory at Jawahar Co-op. Industrial Estate, Plot No. 210/211 Camothe, Panvel-6.
7. M/s. Emirates, Makers Chambers-V, Room No. 221, 2nd Floor, Nariman Point, Bombay-21, including its Office at Kanishka Hotel Room No. 1507, 19, Ashoka Road, New Delhi-1.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments.

[No. S. 35018(9)/86-SS. II]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1986

का. भा. 4061.—मैत्रे-रोलेक्स साईकल इन्डस्ट्रीज, 726-इंड्रियल एरिया-बी लुधियाना-141003 (पं. एन./676) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रांतीय उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिस प्रकार अधिनियम या प्रविधियों का संसार किये बिना हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उद्भावित अनुपूर्वा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुपूर्वा

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसे विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसा सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाप करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्डक के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संवाप, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संवाप आदि हैं; होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब बना उक्त संशोधन किया जाये, तब उन

संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों के प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाप करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिपूर्ण अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उपाययुक्त तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत करे, प्रीमियम का संवाप करने में असफल रहता है और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा अधिनियम के संशोधन में किये गये किसी व्यक्तिकर का दशा में उन भुत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संवाप का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाप तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एन.-35014(258)86-एस. एन.-2]

New Delhi, the 25th November, 1986

S.O. 4061.—Whereas Messrs. Rolex Cycle Industries, 716-Industrial Area-B Ludhiana-141003 (Punjab) (PN/676) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making

any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(258)/86-SS II]

का. आ. 4062-नैमर्-दि दुर्गापुर प्रोपर्टी निमिटेड, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिनिङ्ग, पो. श्री. दुर्गापुर, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल (इस्यू. बी./9206) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अर्जित छूट विधे जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किस्तः पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अर्जित जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निरोध सहित बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अर्जित उन्हें अनुमोदित हैं।

अतः केन्द्रिय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अर्जित रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रिय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के अंदर संदाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अर्जित समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रिय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अर्जित छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संज्ञा करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि, किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वक्ता में संदेय होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिभूत के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपग्रंथों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अवगत अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ब्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह जा सकता है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संशय में किये गये किसी व्यक्तिगत का दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न हो गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों को संशय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उक्त हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[ए. - 35014(257)/86-ए. एस. - 2]

S.O. 4062.—Whereas Messrs The Durgapur Projects Limited, New Administrative Building, P. O. Durgapur, Distt. Burdwan (West Bengal) (WB/9206) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee

legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(257)/86-SS. II]

का.आ. 4063 —मैसर्स पॉलिक्केम लिमिटेड, 45-ए.एस.रो. रोड, गोरगांव, बम्बई-400 062 (एम.ए.ए./1490) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभोग्य हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4724 तारीख 24-11-83 के अनुसरण में और इससे उपायक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1979 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संरक्ष में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आगुता, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समझ-बूझ पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में, जिनके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा दत्त अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, उस उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को अनुसूचना का मास में उससे युक्त बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचार, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है जो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका व.व. आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उक्त फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को

उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि का रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आगुता, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेने की संभावना हो सके, प्रादेशिक भविष्य निधि आगुता, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविद्युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी का रणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अव्यक्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत कर्म की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधित्तारों को जो यदि यह, छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के प्रवर्तन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिवत वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/247/83-पी. एक-2/एस एस-4]

S.O. 4063.—Whereas Messrs Polychem Limited, 45-A, S. V. Road, Goregaon (W), Bombay-400062 (MH/1490) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4724 dated the 24-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions

of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure

prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/247/83-PF-II. SS-II]

का. आ. 4064.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:-

1. मैसर्स सुनील एंड कंपनी, 40 स्ट्रान्ड रोड (चौथी मंजिल) कलकत्ता-1

2. मैसर्स डायग्नोस्टिक्स, 190/8, राश बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता-29

3. मैसर्स फिनले इंजिनियर्स, 4 चान्दनी चौक रोड (प्रथम खंड) कलकत्ता - 72 और इसका 38/1 पूर्णदास रोड, कलकत्ता - 29

4. मैसर्स मानकसिया कंटेनेर्स प्राइवेट लिमिटेड, 15वीं के पास टैम्पल रोड, बेलूर हावड़ा, और इसका 9/3 कोईचौरता पारा सेन, सालकिया हावड़ा स्थित गंडाऊंग तथा 53 राधा बाजार सेन, कलकत्ता - 1 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय

5. मैसर्स कोस्टल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग (प्राइवेट) लिमिटेड 55वीं मिर्जा शासिव स्ट्रीट कलकत्ता-16 और इसकी 204 मंगलम हाऊस राजकाव रोड, नई दिल्ली-15 तथा 46 एक्सचेंज रोड, श्रीनगर-19 स्थित दो शाखाएं

6. मैसर्स वेल्फेयरिस्ट, 26 सेक्सपियर सारन, कलकत्ता-17 और इसकी 227/1 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-20 तथा 3 मंदिर सेन कलकत्ता-16 स्थित सेस और मविम

7. जेम्स प्रोवेर सट्टक्वर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, साइट लेफ्ट सीट सैक्टर-1 कलकत्ता-64 और इसकी पोस्ट ऑफिस और गोपालपुर (कलकत्ता हवाई अड्डे के पीछे) गांव बेरा बाड़ी 24 प्रयत्ना स्थित फंड्री

8. मैसर्स सागर प्राचीण बैंक, आम ताला, कल्या नगर, 24 प्रयत्ना और इसकी 24 प्रयत्ना स्थित 66 शाखाएं।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35017(11)/86 एसएस-2]

S.O. 4064.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Sunil and Company, 40, Strand Road (4th Floor) Calcutta-1.

2. M/s. Diagnostics, 190/8, Rash Behari Avenue, Calcutta-29.

3. M/s. Finlay Engineers, 4, Chandni Chowk Street (1st Floor), Calcutta-72, including its office at 38/1, Purna Das Road, Calcutta-39.

4. M/s. Manaksia Containers Private Limited, 15, B. K. Paul Temple Road, Belur Howrah, including Godown at 9/3, Kaiborta Para Lane, Salkia Howrah, and its Registered Office at 53, Radhabazar Lane, Calcutta-1.

5. M/s. Crystal Advertising and Marketing Private Limited, 55-B, Mirza Ghalib Street, Calcutta-16, including its Branches at (1) 204, Magnum House, Najafgarh Road, New Delhi-15 (2) 46, Exchange Road, Srinagar-19.
6. M/s. Beltronix, 26, Shakespara Sarani, Calcutta-17, including its Sales and service at 227/1 Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Calcutta-20 and 3, Mango Lane, Calcutta-16.
7. M/s. Ober Structures (India) Private Limited, CB-57, Salt Lake City, Sector-1, Calcutta-64, including its factory at Post Office R. Gopalpur (Behind Calcutta Air Port), Village Barabari-24-Paragans.
8. M/s. Sagar Gramin Bank, Amtala Kanyanagar-24-parganas including its 66 Branches located in 24-parganas.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35017(11)/86-SS-II]

का. आ. 4065.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध निमोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत होगी है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

1. मैसर्स लेडो टी कंपनी लिमिटेड, 3-बी लाल बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1
2. मैसर्स कैमियो फेब्रिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड, 127/1 डाक्टर ए. के. पाल रोड, कलकत्ता-34
3. मैसर्स जेफरी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, गारिया मेन रोड, महामाया ताला कलकत्ता - 84
4. मैसर्स मैली सिनेमा, 394, जैसोर रोड डम डम, कलकत्ता-55
5. मैसर्स मिदेश्वर सैन एंड कंपनी (मर्चेंट्स), प्राइवेट लिमिटेड, 33 बिपलाबी राम बिहारी बसु रोड, कलकत्ता-1
6. मैसर्स निपॉन डेनरो इस्पात लिमिटेड, चटर्जी इंटरनैशनल सेंटर (19वीं मंजिल) 33ए जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता-71 और इनकी ए 10/1 कमलेश्वर इंटरनैशनल एरिया, नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित फैक्ट्री
7. मैसर्स एस जी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 71/1ए, पटवा तोना सेन, कलकत्ता-9 और इसका दुर्गा चौक-2 हल्दीया मिदनापुर स्थित साइट कार्यालय
8. मैसर्स यूनाइटेड तार प्राइवेट (प्राइवेट) लिमिटेड, गुरुदास यला गार्डन लेन कलकत्ता-67 और इसका 40/1 स्ट्रांड रोड (दूसरी मंजिल) कलकत्ता - 1 स्थित कार्यालय
9. मैसर्स टीच सर्विसेज 227/1 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-20 और इसकी 51, राधानाथ चौधरी रोड कलकत्ता-15 स्थित साखा
10. मैसर्स एस. के. आयरन इंस्टीट्यूट हावड़ा अमता रोड कलकत्ता पो. आ. नीबरा हावड़ा और इसका 228 नेता जी सुभाष रोड, मन्तगगाची हावड़ा-4 स्थित कार्यालय
11. मैसर्स संगम टेक्स्टाइल्स 61-सी प्राणनाथ चौधरी लेन कलकत्ता-2 और इसका, 50 काटन स्ट्रीट कलकत्ता-7 स्थित कार्यालय
12. मैसर्स ए. बी. यूयुमेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मीसछीला पो. आ. घोषगंगा बैली, हावड़ा और इसका 9/7ए रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट कलकत्ता-9 स्थित कार्यालय

1157 GI/86-5

13. मैसर्स बी. डी. एंड कंपनी, 101, जैसोर रोड कलकत्ता-28 और इसकी 20 पार्क स्ट्रीट स्ट नं. 7 कलकत्ता-16 स्थित कार्यालय
14. मैसर्स पाथर मेसर्स एंड सर्विसेज "कोनर्स हाउस" 2 गणेशचन्द्र एबन्यू, कलकत्ता-13 और इसका 3 भैरव लेन कलकत्ता-1 स्थित कार्यालय
15. मैसर्स एलास्टोलेन इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू जैसोर रोड, गंगानगर, 24 प्रगता और इसका 401 अन्नपूर्णा 12 ए लाई सिन्हा रोड कलकत्ता-71 स्थित कार्यालय
16. मैसर्स ग्रामुमीनियम प्रोटेक्शन कंपनी, 105/1, उल्हा बांगा, मेन रोड, कलकत्ता-67
17. मैसर्स नार्यन, फाक्टर्स (इंडिया) 12/3 बी गिरीश घोष रोड, बेनूर मठ हावड़ा
18. मैसर्स दी कोल ऑर्गेनाइजेशन एम्पाईज (भारत सरकार) कोप्रेटिव स्टोर लिमिटेड, 1, कौसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-1
19. मैसर्स इंडिया ब्रुक डिस्ट्रीब्यूटर्स 13 के आई डी स्ट्रीट (पहिली मंजिल) कलकत्ता-16
20. मैसर्स यान्त्रिक उद्योग 6ए, केनाल रोड, कलकत्ता 53

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35017(10)/86 एस एस - 2]

S.O. 4065.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M/s. Sledo Tea Company Limited 3-B, Lal Bazar Street, Calcutta-1.
2. M/s. Cassio Fabricators Private Limited, 127/1 Dr. A. K. Pal Road, Calcutta-34.
3. M/s. Zephyr Pharmaceutical Private Limited, Garia Main Road, Mehamaoyatala, Calcutta-84.
4. M/s. Shelly Cinema, 394, Jessore Road, Dum-Dum, Calcutta-55.
5. M/s. Siddessur Sen and Company (Merchants) Private Limited, 33, Biplabi Rash Behary Boshu Road, Calcutta-1.
6. M/s. Nippon Denro Ispat Limited, Chatterjee International Centre, (19th Floor) 33-A Jawaharlal Nehru Road, Calcutta-71 and Factory at Nagpur (Maharashtra).
7. M/s. S. G. Construction Private Limited, 71/1A Patuatola Lane, Calcutta-9 including its site Office at Durgachak-2, Haldia Midnapore.
8. M/s. United Tar Products (Private) Limited, Gurudas Dutta Garden Lane, Calcutta-67, including its Office at 40/1, Stand Road, (2nd Floor), Calcutta-1.
9. M/s. Teeh Services, 227/1, Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-20 including its branch at 51, Radhanath Choudhury Road, Calcutta-15.
10. M/s. S. K. Iron Industries, Howrah Amta Road, Kantalia, P. O. Nibra, Howrah including its office at 228 Netaji Subhash Road, Santragachi, Howrah.
11. M/s. Sangam Textiles 61-C, Prannath Choudhary Lane, Calcutta-2, including its office at 50, Cotton Street, Calcutta-7.

12. M/s. A. B. Pneumatic, Pvt. Ltd. Village Nischinda, P. O. Ghosh Para, Bally, Howrah including its Office at 9/7A Ramanath Mazumdar Street, Calcutta-9.
13. M/s. B. D. & Co., 101 Jessore Road, Calcutta-28 including its Office at 20, Park Street, Suit No. 7, Calcutta-16.
14. M/s. Power Sales & Service "Commerce House" 2, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13, including its office at 3, Mangee Lane, Calcutta-1.
15. M/s. Elastolan Engineers Pvt. Ltd., New Jessore Road, Ganga Nagar 24-Pataganas including its Office at 401, "Annapurana" 12-A, Lord Sinha Road, Calcutta-71.
16. Aluminium Products Co., 105/1, Ultadanga Main Road, Calcutta-67.
17. M/s. Iron Crafts (India) 12/3-B, Girish Ghose Road, Belurmath, Howrah.
18. M/s. The Coal Organisation Employees (Government of India) Co-operative Stores Ltd. 1. Council House, Street, Calcutta-1.
19. M/s. India Book Distributors, 13 Kyd Street (1st Floor) Calcutta-16.
20. M/s. Yantrik Udyog, 6-A, Canal Road, Calcutta-53.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35017(10)|86-SS. II]

का.अ. 4066.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

1. मैसर्स जंगी इन्डस्ट्रीज, एस-38, इन्डस्ट्रियल एरिया, जालंधर
2. मैसर्स सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, भालवा पिक्चर पैलेस कम्प्लेक्स, पटियाला
3. मैसर्स सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ट्रेन, जो. टी. रोड, बाई पास, जालंधर
4. मैसर्स हरबंस सिंह मिश्र कंस्ट्रक्टर, 2619, मोहना चौक, भटिन्दा
5. मैसर्स टेलीफोन केबल (पंजाब) लिमिटेड एस.सी.ओ.नं. 8283 सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ और इसकी ग्राम कुनेवाल, तहसील गढ़शंकर कस्बा होसियारपुर में स्थित फैक्ट्री।
6. मैसर्स पंजाब आनन्द लैम्प इन्डस्ट्रीज लिमिटेड फेज-IX मोहली एम.ए. एस. नगर मोहली-8 कम्प्लेक्स, पो. आ. माडोली कस्बा रोपड़ पंजाब और इसकी एम. सी. ओ. 112, 113, सेक्टर 8 सी चंडीगढ़-1 स्थित फैक्ट्री।
7. मैसर्स पंजाब वेरामिक्स लिमिटेड पो. बा. नं. 36 डेबवाली रोड, बटिन्डा और इसका 28 नेहरू प्लेस नई दिल्ली स्थित कार्यालय
8. मैसर्स शिव कुमार कसन कंस्ट्रक्टर मैडिमन सेल सेंटर, गांधी मार्केट, बटिन्डा
9. मैसर्स प्रताप गुहम कैरियर्स प्रताप स्टेट, चेहेरता, अमृतसर
10. मैसर्स एक्सन इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज, सामराला

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(175)/86-एस एस-2]

SCO. 4066.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Jaggi Industries, S-38, Industrial Area, Jalandhar.
2. M/s. Sanraj Foods Private Limited, Malwa Picture Palace Complex, Patiala.
3. M/s. Central Institute of Hand Tools, G. T. Road, Bye Pass, Jalandhar.
4. M/s. Harbans Singh, Civil Contractor, 2619, Mohna Chowk, Bhatinda.
5. M/s. Telephone Cables (Punjab) Limited SCO No. 82-83, Sector 17-C, Chandigarh, including its factory at Village-Kulewal, Tehsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
6. M/s. Punjab Anand Lamps Industries Limited Phase-IX Mohali, S.A.S. Nagar, Mohali VIII, Kambala, Post Office Manauli, District Ropar, Punjab, including its factory SCo-112-113 Sector 8-C, Chandigarh.
7. M/s. Punjab Ceramics Limited, P. B. No. 36, Debwali Road, Bhatinda-151001, including its office at 28, Nehru Place, New Delhi
8. M/s. Shiv Kumar Kansal, Contractor, Medicine Sale Centre, Gandhi Market, Bathinda.
9. M/s. Partap Goods Carriers, Partap Estate, Chheharta, Amritsar.
10. M/s. Ekson Engineering Industries, Samrala.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(175)|86-SS-II]

का. अ. 4067.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स कृष्णा कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज 90/70 जालंधर रोड, बलवा ग्रहमदाबाद-45,
2. मैसर्स नरेन्द्र इन्जिनियरिंग वर्कस, सी-1सी, 42/2 जालंधर रोड, सी नन्देखरी, जिला बडोदा।
3. मैसर्स आशा टेक्स्टाइल, रोड नं. 3 बी-55, उग्राला, सूरत
4. मैसर्स द ग्लोबल मार्केटाइंग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धनजी भाई कम्पाउन्ड, भद्रा, अहमदाबाद।
5. मैसर्स एससी एचओ ईक्यूपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आकिस डिवाइज, रोड, अष्टाविया बिलेज, बिस्न मोरा और इसकी बम्बई स्थित शाखा।
6. मैसर्स गुजरात हिमालय निमेट्स लिमिटेड, जीवन ज्योन, राम जी रोड, पोरबंदर और इसकी धामपुरा ग्राम में स्थित फैक्ट्री।
7. मैसर्स गुजरात मटको कौनैव लिमिटेड बडोदा गोधरा हाई वे कालोन जिला पंचमहल और इसका केयर आफ वीस्टन इंजीनियर्स वर्क्स 54 ए सारखेत रोड नजदीक फिनम सेंटर बम्बई स्थित कार्यालय
8. मैसर्स अमित अलकोहल एण्ड कार्बन डायी ओकसाइड लिमिटेड नैशनल हाई वे नं. 8 बापी जिला वलसाड और इसका बम्बई स्थित प्रशासनिक कार्यालय

9. मेसर्स पटेल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 216 आजाद सोसाइटी अम्बावादी, अहमदाबाद
10. मेसर्स जेवरचन्द एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड, पादरा रोड, बड़ोवा ।
11. मेसर्स वुविंग पब्लिकेशन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड सरस्वती भवन सुखराम नगर के पीछे, कोपनीपुरा अहमदाबाद ।
12. मेसर्स वी सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वाला जो रोड सूरत
13. मेसर्स बड़ोवा सरफेस प्रोटेक्शन सर्विस, परनेरा पोस्ट आफिस अटुल, जिला वलसाद
14. मेसर्स दीप ज्योति ट्रेडर्स, 2335 सैयद मस्जिद, दोलत खाना, सारंग पुर, अहमदाबाद
15. मेसर्स बड़ोवा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इन्डस्ट्री-यल स्टेट गोरवा रोड, बड़ोवा
16. मेसर्स कनीशा स्टील्स, वल्लभ विद्यानगर
17. मेसर्स शाहजन्दा तम्बाकू कम्पनी, सबोवा जिला बड़ोवा
18. मेसर्स अनुपम अधिषिष, 159 त्रिवल उद्योग नगर, वल्लभ विद्यानगर-20

अतः केन्द्रिय सरकार उक्त निरम का धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध अन्तर्गत स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(176)/86-एस.एस.-2]

S.O. 4067.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Krishan Chemical Industries, 90/17, GIDC Estate, Vatva, Ahmedabad-45.
2. M/s. Narinder Engineering Works, C-I, B, 42/2, G.I.D.C. Nandesari, District Baroda.
3. M/s. Asha Textile, Road No. 3-B-55, Udhna, Surat.
4. M/s. The Relief Mercantile Co-operative Bank Limited, Dhanjibhai Compound, Bhadra, Ahmedabad.
5. M/s. Aspee Agro Equipment Private Limited, Office Chikhali Road, Antalia Village, Bilimora, including its branch at Bombay.
6. M/s. Gujarat Himalaya Cement Limited, Jeevan Jyot, M. G. Road, Porbander-75, including its factory at Village Dharampur.
7. M/s. Gujarat Setco Clutch Ltd., Baroda Godhra Highway Kalol District Panchmahal, including its Office at Bombay-34.
8. M/s. Amit Alcohol and Carbon Dioxide Limited, National Highway, No. 8 Vapi Distt. Vasad, including its administrative office at Bombay-34.
9. M/s. Patel Construction Company, 216, Azad Society, Ambawadi, Ahmedabad.
10. M/s. Zevarchand Export Pvt. Ltd., Padra Road, Baroda.
11. M/s. Booking Publications and Trading Company Limited, Saraswati Bhavan Building Behind Sukhaam Nagar, Gomitpur, Ahmedabad.
12. M/s. The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Limited, Balaji Road, Surat.
13. M/s. Baroda Surface Protection Service Parnera, P.O. Atul Distt. Valsad.

14. M/s. Dipjyot Traders, 2335, Saiyed Masjid, Dolat Khana Sarangpur, Ahmedabad.

15. M/s. Baroda Industrial Development Corporation Limited, Industrial Estate, Gorwa Road, Baroda.

16. M/s. Kanisha Steels, Vallabh Vidyanagar.

17. M/s. Sahjananda Tobacco Company, Sokhda District, Baroda.

18. M/s. Anoopan Adheshives 159, Vithal Udyognagar, Vallabh Vidyanagar-20.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(176)/86-SS. II]

का. आ. 4068.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मेसर्स केटी सी टायर (इंडिया लिमिटेड) पो. आ. एफिरायदी, 18/402, पो. बा. नं. 555 कन्नाए रोड, कालोहट ।
2. मेसर्स जमुना कल्ड, केवर आफ मयुरा कोटस लिमिटेड, कोराटी, लिचुर कस्बा ।
3. मेसर्स कुण्यपाराम्बा पावर लूम वीवर्स इन्डस्ट्रियल (वर्कशाप) को-ओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पो. आ. मामबाराम केसूर कस्बा ।
4. मेसर्स डा अन्जारा कृष्ण कोशरोनेवका को ओ. सोसाइटी लिमिटेड, नं. सी-22 (डी.) पो. ऑ. भुसापाला ।
5. मेसर्स संघी एण्ड कम्पनी केसूर स्टेशन रोड और इसकी टेलीवेरी, पायनूर और तालीपाराम्बा स्थित शाखाएं ।
6. मेसर्स कुण्यपाराम्बा को-ओपरेटिव सरल बैंक लिमिटेड, नं. एफ-1201 पो. आ. कुण्यपाराम्बा, टेलीवेरी ताल्लुक, केनूर कस्बा और इसकी माखामबई और केलाचूमाला स्थित शाखाएं ।
7. मेसर्स श्री कृष्णा इम्प्लामेंट सोलनूर-2 ।
8. मेसर्स धरमोचिल इन्डस्ट्रीज वी वी 2, इन्डस्ट्रियल स्टेट कानागाप्पी, कल्लन-690518
9. मेसर्स कैसूर श्री नारायण कालिज स्टुडेंट को-ओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पो. आ. थोटाडा कैसूर ताल्लुक एण्ड कस्बा ।
10. मेसर्स सैन्टरल इन्सटीट्यूट आफ फिशरिज, टैकनोलाजी डिपार्टमेंट कैन्टीन, मत्सयापुरी, कोचीन
11. मेसर्स टिफिन रूप टाइट "ए" नम्बर-21 पार्टी (एस सी) सर्वे आफ इन्डिया वालाकाबावो पो. आ. त्रिवेन्द्रम-695008
12. मेसर्स सी.ओ. जानी कान्ट्रैक्टर सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग, कारपोरेशन पुथोले लिचुर-4
13. मेसर्स के. जे. ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, वेलीमन (पो. ओ. कुयरा कल्लन कस्बा)
14. मेसर्स टेलीग्राफ कैन्टीन सैन्ट्रल टेलीग्राफ आफिस मदनवेरी, कोचीन-1
15. मेसर्स ऐनकीकल ट्रेडर्स एण्ड फाहनासर हनीडीप, प्लामुड, त्रिवेन्द्रम, और इसके (1) ओमालूर (2) पठानामिहा (3) कल्लम (4) छेगानूर स्थित कार्यालय ।
16. मेसर्स डिपार्टमेंटल टिफिन रूम, आफिस आफ फ्री डिवाइजल इन्जिनियर कोखल मॉडिनेस, एरनाकुलम कोचीन-16

17. मैसर्स माजी काजी एंड कम्पनी, न्यू रोड कोचिन-2 मयनचेरी गांव, कोचिन तालुक अरनाकुलम कस्बा
18. मैसर्स कैमनी होटल्स लिमिटेड कोकालई, त्रिचुर
19. मैसर्स रामाकृष्णा ट्रांसपोर्ट पी. आ. मुझापपाला-15
20. मैसर्स फूड, क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट कानामामरी अलवे थरीकाकरा विलेज कन्यानूर तालुक अरनाकुलम कस्बा और इसका कान्पीकत स्थित एक्सटेंशन सेंटर
21. मैसर्स थाम्पानूर वाहन्स, फोरन लिक्वर रिटेल शॉप नं.-2, थारिसेटा जंक्शन त्रिवेन्द्रम
22. मैसर्स नेशनल डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी, 39/395 अरणाव कास रोड अरनाकुलम काचिन, कन्यानूर तालुक अरनाकुलम कस्बा
23. मैसर्स ऐडवांराम कासीरोपादकी सहकारनासंगम लिमिटेड, नं. डो 63(बी) पी. आ. एडवांराम-73 कोकोनाड कस्बा
24. मैसर्स पुझापी वांस एन्ड इन्स्ट्रियल (इश्यू एस) को-ओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पी. आ. कोटाली कन्नूर डिस्ट्रिक्ट और तालुक पुझापी पंचायत।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 1, को उप धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थानों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(177)/86-एम.एम-2]

S.O. 4068.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. K.T.C. Tyres (India) Ltd., P. O. Alkarapadi, 18/402, P.B. No. 555, Kallai Road, Calicut.
2. M/s. Jumna Club, C/o Madura Coats Ltd., Koratti, Trichur District.
3. M/s. Kuthuparamba Power Loom Weavers Industrial (Work Shop) Co-operative Society Ltd, P.O. Mambaram Cannanore District.
4. M/s. The Anjarakandy Ksheeroopedaka Co-operatives Society Ltd., No. C-22 (D) P.O. Muzhappala.
5. M/s. Sangi and Co. Cannanore Station Road including its Branches at (1) Tellicherry (2) Payyanur (3) Taliparamba.
6. M/s. Kuthu Paramba Co-operatives Rural Bank Ltd., No. F, 1261, P.O. Kuthuparamba, Tellicherry T.K. Cannanore Dist. including its branches at Maruvambai and Kolathumala.
7. M/s. Sree Krishna Implements, Shornur-2.
8. M/s. Thermochil Industries, B-1-B-2, Industrial Estate Karunagappally Quilon.
9. M/s. The Cannanore Sree Narayana College Students and Co-operative Society Limited, P.O. Thottade Cannanore Taluk and District.
10. M/s. Central Institute of Fisheries, Technology Departmental Canteen Matsyapuri, Cochin.
11. M/s. Tiffin Room Tyre 'A' No. 21, Party (S.C.) Survey of India, Vallakkadavu P.O. Trivandrum.
12. M/s. C. D. Johnny Contractor, Central Ware Housing Corporation, Puthola, Trichur-4.
13. M/s. K. J. Trading Company Private Limited, Vellimon (P.O.) Kundara Quilon Dist.
14. M/s. Telegraph Canteen Central Telegraph Office, Mattancherry, Cochin-2.

15. M/s. Amanical Traders and Financiers, Honeydov Plamoodu Trivendrum-4 including its offices at, (i) Omalloor (ii) Pathanamthitta (iii) Quilon and (iv) Chenganoor.
16. M/s. Departmental Tiffin Room office of the Divisional engineer Coaxial Maintenance Ernakulam Cochin-16.
17. M/s. Mawaji Kanji and Company, Now Road, Cochin-2, Mattanacharri, Village, Cochin Taluk, Ernakulam Distt.
18. M/s. Casino Hotels Limited, Kokkalai, Trichur-1.
19. M/s. Ramakrishna Transport, P.O. Muzhappala, 15.
20. M/s. Food Craft Institute, Kalamassery Alwaye Thrikakra Village Kanyannur Taluk Ernakulam District, including its Extension Centre at Calicut-5.
21. M/s. Thampanoor Wines, Foreign Liquor Retail Shop No. 2, Aristo Junction, Trivandrum.
22. M/s. National Distributing Company, 39/795, Arangath Cross Road, Ernakulam, Cochin Kanayannur Taluk Ernakulam Dist.
23. M/s. Adivaram Ksheeropadaka Sahakarana Sangham Limited, No. D. 63 (D) Post Office Adivaram 73, Kozhikode Distt.
24. M/s. Puzhathi Weavers Industrial (W.S.) Cooperative Society Limited P.O. Kottali Connanore Dist. and Taluk Puzhathi Panchayat.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(177)/86-SS. II]

का.आ. 4069.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स माफ्ती उद्योग लिमिटेड, पालम गुडगांव रोड, गुडगांव हरियाणा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अगस्त, 1986 से 31 जुलाई, 1987 तक जिसमें यह लागू भी सम्मिलित है एक वर्ष की अवधि के लिये छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का निरोधक उस अवधि का वाहन जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की वाहत देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरोधक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—
 - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिये दी गई किसी विवरणियों की विशिष्टियों को मर्यापित करने के प्रयोजनों के लिये; या
 - (ii) यह अभिविधित करने के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा प्रेषित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रखे गये थे या नहीं; या
 - (iii) यह अभिविधित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो

ऐसी प्रमुखियाएँ हैं जिनके प्रतिकलस्त्रण इस अधिसूचना छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

- (iv) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनों के लिये कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में रजिस्ट्रार के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उद्देश्यों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा :—

- (क) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उनके भारतीय अधिकारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संचय से संबंधित ऐसे लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दें जो वह आवश्यक समझे; या *
- (ग) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक की, उनके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाये, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संज्ञा एस-38014/56/86-एस.एस.-I]

स्पष्टीकरण शापन

इस मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4069.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts M/s. Maruti Udyog Limited, Palam Gurgaon Road, Gurgaon, Haryana, from the operation of the said Act for a period of one year with effect from 1st August, 1986 upto and inclusive of the 31st July, 1987.

2. The above exemption in subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in receipt of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—
- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to :—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/56/86-SS.I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

का.प्र. 4070.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, मैमर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, डाकघर—बर्ली दादरी, जिला बिजानो, हरियाणा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 8 अक्टूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की अवधि के लिये छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, यर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शाये गये होंगे;
- (2) उक्त छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुखियाएँ प्राप्त करने रहेंगे, जिनका पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत्त अधिसूचियों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिये यदि कोई अधिसूचना पहले ही संवत्त किये जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किये जायेंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की यावत् जिसके दौरान उन कारखाने में उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे

इसमें हमने पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रत्येक में और ऐसी विनिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

- (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विनिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिये, या
- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा बना अंतिम रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रखे गये थे या नहीं, या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमाणियों का, जो ऐसी प्रमाणियां हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नक़्क़ प्रारंभ रूप में पाने का हक़दार बना हुआ है या नहीं; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि उन अवधि के दौरान, जब उक्त कारख़ाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपायों का अनुगमन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक ने यह घोषणा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिनियम में के कारख़ाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारनायक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संबंध से संबंधित ऐसे लेखा बहिन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारियों के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको परोक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उनके अधिकार या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारख़ाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाये, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारियों के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परोक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारख़ाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबहिन या अन्य दस्तावेज की नक़्क़ करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/46/86-एन.एन.-I]

स्पष्टीकरण शायद

इस मामले में छूट को भूतलकी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलकी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 26th November, 1986

S.O. 4070.—In exercise of the power conferred by section 88 read with section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of M/s. Cement Corporation of India Limited, P.O. Charkhi Dadri, District Bhivani Haryana from the operation of the said Act for a period with effect from 8th October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;
- (2) Notwithstanding this exemption the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[S-38014/46/86-SS. I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time/received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

का. प्रा. 4071:—जयन्त पैकेजिंग प्रा. लि. सुपर 12 और 13, इण्डियन एस्टेट, गुन्डी मद्रास—600032 (टी. एन/3028) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिप्राय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सङ्ग्रह बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजय है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपलब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्रिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रारंभों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3(क) के अन्तर्गत के अधीन समय-समय पर निर्रिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रमारों संशय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि, का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी यावत् आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्स करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रदीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के परावर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी नाररीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के यंत्री कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उन नियत नाररीय के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यर्थपत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उस पुन पदस्रो के नाम निर्देशिनीयां या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनीयां विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय नगरना से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एन-35014 (260)/ 86 एस एस-2]

S.O. 4071.—Whereas Messrs Jayant Packaging Private Limited, Super-A, 12 and 13, Industrial Estate, Guindy Madras-600032 (TN/3028) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed, hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(260)/86-SS. II]

का. प्रा. 4072 —मैसर्स टी. सार्वेम को-ओपरेटिव स्पिनिंग मिल लि., के. एन. क.मोती, सार्वेम-836019 (टी. एन. / 4900) (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक भविष्य या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप संग्रह बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 2317 तारीख 6-5-1986 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उक्त नम सूरत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सन्तुष्ट करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि को जाने का अवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्धेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्दिष्टितों की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडू के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविधायुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अग्रिम नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यक्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

इच्छा एस-35014/114/83-पी.एफ.-2/एसएस2]

S.O. 4072.—Whereas Messrs The Salem Co-operative Spinning Mills Limited, K.N. Colony, Saleem-636014 (TN/49000) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2317 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-5-1986 upto and inclusive of the 26-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

1157 GI/86—6.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/114/83-PF-II SS. II]

का.आ. 4073.—मैसर्स म्यूजिक इन्डिया लि., स्ट्रालिंग सेंटर, दूसरी मंजिल डा. अरु वसन्त रोड, बम्बई (एम.एच./4464) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

भारत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.भा. 4029 तारीख 15-10-83 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 29-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास के समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभावों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिमय अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों

को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक वृत्ति में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(191)/83-पी एफ-2/एम एम-2]

S.O. 4073.—Whereas Messrs Music India Limited, Sterling Centre 2nd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay (MH/4464) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4029 dated the 15-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-10-1986 upto and inclusive of the 28-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No.S-35014/191/83-PF.II-SS-II]

का.प्रा. 4074.—सैसर्स एमटीसी इंजीनियरिंग लि. (जो पहले दी मिलिंग ट्रेडिंग कम्पनी लि. के नाम से जाना जाता था)। भानन्द, सोबीतारा रोड, बी.बी. नगर-388120, अहमदाबाद (जी.जे./4864) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है; और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अधिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निषेध महशुद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 3959 तारीख 1-10-1983

के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 से तीन वर्षों के अवधि के लिए जिसमें 21-10-1989 की सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसा मुविद्याएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्रिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारो का प्रारंभ ना तो समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन गमय-पत्र पर निर्रिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रगपन में, जिनके अन्तर्गत नेत्राओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-नोट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज होगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम की सन्वत् करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस रकम कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्दाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन भुक्त सदस्यों के नामनिर्देशनितियों या विधिक वारिसों को जो याव यह, छूट न दा गइ हाता तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदा के सन्दाय का उत्तरदायक नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बांनोक्त राश के हकदार नामान्वेषी/विधिक वारिसा का उस राश का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाव का प्राप्ति के एक मसि के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एत-35014(151)/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 40/4.—Whereas Messrs Lmici Engineering Limited (formerly known as the Milling Trading Company Limited) Andam Sogama Road, V. V. Nagar, 386120, Ahmedabad (Gujarat) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3959 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as provided by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary

premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/151/83-PF.II-SS-II]

का. आ. 4075.—मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि, मधुबन-55, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (श्री.एल./4869) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपग्रन्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पूर्णकृषि व्यवसाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहायक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3947 तारीख 8-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-11-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-11-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्वाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का सन्वाय आदि भी है, इन सबी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम से किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उग रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्दाय होती जहाँ वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिपूर्ण अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, योगाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उक्त राशि का सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(233)/82 पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 4075.—Whereas Messrs Hindustan Fertilizers Corporation Limited, Madhuban-55, Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/4869) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3947 dated the 8-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-1985 upto and inclusive of the 26-11-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as provided by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/233/82-PF-II-SS-II]

का. प्रा. 4076 :— मेसर्स श्री आम्बिका मिल्स लि., (ग्रामिका टयर्स की यन्टि) बात्वा, जिला, अहमदाबाद (जी. जे./4457) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हमें हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अग्रिमदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी विशेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 4567 तारीख 18-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 17-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिनमें 16-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के उपबन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गृहराज को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निराकरण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा स्कीम प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तथा उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के तृचत्वारिंशत् पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाने हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उमरकम से कम है जो कर्मचारी को उमर दशा में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गृहराज के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुमित-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियम तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकृत क, वषा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वामा फायदों के सन्दाय का उत्तरवाधिय नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशनी/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीन सुनिश्चित करेगा।

[सख्या एस-35014(202)/83-मा.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 4076.—Whereas Messrs Shri Ambica Mills Limited (Unit Ambica Tubes) Vatva, District-Ahmedabad (GJ)4457 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4567 dated the 18-11-1983 subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17-12-1986 upto and inclusive of the 16-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the em-

ployees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/202/83-PF-II-SS-II]

का. घा. 4077 :—वि टिनप्लेट कं. 'ग्राफ इन्डिया लि.', गोवर्धपुरी, जमशेदपुर (बी. घा. 2) (जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही वि टिन प्लेट कं. ग्राफ इन्डिया लि. की लाईफ कवर स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवर्द्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुसूची हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 क द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावर्द्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सर्वा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, विहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड -क के अधीन समय समय पर निविष्ट करे।

3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का दहसंख्या क भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पक्षेहीन सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बावत आवश्यक प्रीमियम बैंक में लाईफ कवर स्कीम के खाते में जमा करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि किये जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमेय हैं।

7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिका को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

7 लाईफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, बिहार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी दि टिनप्लेट कं. आफ इण्डिया लि. की लाईफ कवर स्कीम के, जिसे स्थापन पक्षेय अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी प्रति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो दि टिनप्लेट कं. आफ इण्डिया लि., जमशेदपुर नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में अक्षम रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किय गये किसी व्यतिक्रम का दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिकाओं या विधिक वारिसों को को जो यदि यह छूट न बं गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मरु होने पर उस के हकदार नाम निर्देशिकाओं/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय व्यवस्था में और प्रत्येक

या में स्कीम के खाते में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014(259)/86-एम एम-2]

S.O. 4077. -Whereas Messrs. Tinsplate Company of India Limited, Golmuri, Jamshedpur-831003 (BR/2) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of Tinsplate Company of India Ltd., Jamshedpur in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Bihar and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme and pay necessary premium in respect of him to the S.B. A/C of Life Cover Scheme of M/S. Tinsplate Company of India Limited, Jamshedpur.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and no amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of M/S. Tinsplate Co. of India Ltd., Jamshedpur, as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the M/S. Tinsplate Company of India Ltd., Jamshedpur, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the account of the Life Cover Scheme.

[No. S. 35014(259)86-SS-II]

का. धा. 4078—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए—

1. मैसर्स हौसिट्रिल डिस्टिल्लेंट कम्पनी, पी. आ. माकम जंक्शन, कस्बा डिब्रुगढ़
2. मैसर्स कामरुपा एंटरप्राइज, ए. टी. रोड, टोकोबारी गोहाटी-8
3. मैसर्स डिपार्टमेंटल कैंटीन, रिजनल रिसर्च लाइब्रेरी, जोरहट-6
4. मैसर्स माइन ब्लैक स्मिथी यूनिट, धरमनगर नार्थ, त्रिपुरा
5. मैसर्स कामाख्या उद्योग, बिरकुची, नारंगी, गुहाटी-26
6. मैसर्स परसुराम सिमेंट लिमिटेड, (अरुणाचल प्रदेश के अन्तर्गत) पी. ओ. तेजु-1 कस्बा लोहत (अरुणाचल प्रदेश)
7. मैसर्स ग्लोब (इन्डिया) लिमिटेड श्रीमन्ता मार्केट ए. टी. रोड गोहाटी-1 और इसका कलकत्ता स्थित स्थानीय कार्यालय
8. मैसर्स कैपिटल कैरिंग कम्पनी (प्रा. लिमिटेड) पी. आ. थाना रोड तिनसुकिया-786125 कस्बा डिब्रुगढ़

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(178)/86-एस.एस.-2]

S.O. 4078.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respectively establishments, namely,

1. M/s. Hocitril Distillant Co., P.O. Makum Junction, Distt., Dibrugarh, Assam.
2. M/s. Kamrupa Enterprise, A.T. Road, Tokobari, Gauhati-8.
3. M/s. Departmental Canteen, Regional Research Laboratory, Jorhat-6.

4. M/s. Model Blacksmithy Unit, Dharamnagar, North Tripura,
5. M/s. Kamakhya Udyog, Birkuchi, Narangi, Gauhati-26.
6. M/s. Parasuram Cement Limited, (Government of Arunachal Pradesh Undertaking), P.O. Tezu-792001, Dist. Lohit, Arunachal Pradesh.
7. M/s. Globe (India) Ltd., Sheomanta Market, A.T. Road, Gauhati-1 including its Regl. Office at Calcutta-1.
8. M/s. Capital Carrying Company (Private) Limited, P.O. Thana Road, Tinsukia-786125, Dist. Dibrugarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(178)86-SS-II]

का. धा. 4079.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए—

1. मैसर्स उपा इन्स्टीज बोर्ड मिल, सिधुराबापुरम (बाया सिवाकासी)
2. मैसर्स आर एन सामी बोम्बे ड्राइनिंग शो रूम 302—303 सत्यामूर्ति रोड, अरीन
3. मैसर्स दी मद्रास टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट स्टोक को-ओपरेटिव स्टोर टेलीफोन हाऊस, मद्रास
4. मैसर्स टी. बी. डी-53 सी सोरपानन्धन मिल्क प्रोड्यूसर को-ओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सी. सोरपानन्धन चेमलम तालुक एन ए कस्बा
5. मैसर्स प्रलवध फर्मासिटिकल (प्राइवेट) लिमिटेड, 5, चन्ना बाग एम्प्लू, डाक्टर राधा कृष्णन रोड, मद्रास
6. मैसर्स रमन इन्स्टीज 44/8 पूतामलाए रोड, मद्रास
7. मैसर्स वा नैशनल स्टील फैन 125 प्रथम मंत्राल, एल्लामस रोड, मद्रास
8. मैसर्स इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर सर्विस डिवाइजन, 781 अन्नासलाए, मद्रास
9. मैसर्स के. बी. आर, ट्राम्पपोर्टिंग नं. 1, वैक्टरमीयार स्ट्रीट, मद्रास
10. मैसर्स प्रकैक्ट प्रेस प्रोड्यूसर्स, नं. 16 लेक विजु रोड, मद्रास
11. मैसर्स मैट्रो इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज, 3/बी-1 स्मिथ लेन, माऊन्ट रोड, मद्रास
12. मैसर्स अरविटेक पोलिमोटक प्राइवेट लिमिटेड, एन-5 सिवको इन्डस्ट्रियल स्टेट विलेजकम मद्रास-49 और इसका 15 राजारतनम स्ट्रीट कुलवाक मद्रास-10 स्थित स्थानीय कार्यालय
13. मैसर्स यूनाइटेड फर्म सर्विस, नं. 5 कृष्णाबा मिस्ट्री स्ट्रीट बुड रोड मद्रास-2 और इसका नं. 163 कोडामवाकाम हाई रोड, मद्रास 34 स्थित स्थानीय कार्यालय
14. मैसर्स कृष्णा इन्टर प्राइजिज, अब्दुल रजाक स्ट्रीट, सीमबापुर मद्रास-15 और इसका मद्रास-2 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय

15. मैसर्स क्यूज धियर इलेक्ट्रिक लिमिटेड, चाङ्गलाम गांव थिपेरम्बुर तालुक चिंगलपुट कस्बा और इसका सं० 149 पुनामलाए हाई रोड अमीन ओ कराए मद्रास 29 स्थित स्थानीय कार्यालय
16. मैसर्स मेरिडियन कार्मिनिटीकल (प्राइवेट) लिमिटेड, और इसकी पी पी भ्रमान कोयल स्ट्रीट चोरमपट मद्रास-44 स्थित फैक्ट्री तथा मद्रास-43 स्थित स्थानीय कार्यालय
17. मैसर्स विष्णु अग्नि फरलेम काम्पोनेटम (प्राइवेट लिमिटेड) नं. 5, मिडको इन्डस्ट्रियल स्टेट मद्रास-49 और इसके ए-13 द्वितीय ऐवेन्यू अन्नामगर मद्रास-40 स्थित प्रशासकीय कार्यालय
18. मैसर्स चोपरो लेबर रु. 232 एन एम सी बोम रोड मद्रास 1 और इसकी 245-ए तथा बी चिदंबरम एवेन्यू कनकसा-6 स्थित शाखा
19. मैसर्स काली कम्पोजिट मेटल 4216 सी मद्रास रोड मेना कावेरी कुम्भ कोनाम और इसका 318 माउन्ट रोड टेनाम्पेट मद्रास-18 स्थित होटम
20. मैसर्स साऊथन स्टील इन्डस्ट्रीज 205/2 जी एम टो रोड धोतरे गांव बाम्बालूर मद्रास-48 और इसका नं. 2, अटको कालोनी अलदूर मद्रास-16 स्थित प्रशासनिक कार्यालय
21. मैसर्स तमिलनाडू पुनिम हाउसिंग कारपोरेशन पेरियार विल्डिंग मद्रास और इसकी (1) तिरुचिरापली (2) कोयम्बदूर और (3) पालायमकोटई स्थित शाखाएं
22. मैसर्स वा स्वामीपाली मिल्क इन्डलूम वीवरस को-प्रोपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड मेल सोसाइटी लिमिटेड, तिरुमान जाना स्ट्रीट स्वामीपाली, और इसके (1) द्विती (2) कोम्बा-कोनाम (3) तिरुमुवानाम (4) नेवली स्थित चार गो रूप
23. मैसर्स सीटू मॅक इन्डस्ट्रीज 8/139 सी इन्डिंगम राए (राया सलूट) और इसका 72, जावलीवाडए स्ट्रीट निवाकाजी स्थित प्रशासनीय कार्यालय
24. मैसर्स एन. एन. 36 रामानन्ध डिस्ट्रिक्ट फिशरमैन को-प्रोपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, वलीपत्तम पोस्ट रामानाया-पुरम और इसकी थॉड। और पोतवन में स्थित शाखाएं
25. मैसर्स तीरुज इन्टर प्राइजिज, 5, कामराज पार्क लेन मद्रास-13 और इसका 40 पेडीअर कोएल स्ट्रीट मद्रास स्थित प्रशासनिक कार्यालय
26. मैसर्स फाटोमोटिव ट्रेडर्स, 17, वेगम साहिब बूसरी लेन अन्नामलाए, मद्रास और इसकी 52, 11 कास जतलिट्ट कालोनी, बंगलौर स्थित शाखा
27. मैसर्स वा कुन्ना कुशी भारती इन्डस्ट्रियल को-प्रोपरेटिव फैक्ट्री लिमिटेड, कुन्नाकुशी और इसकी सतूर और कोन्निमयट्टी स्थित दो शाखाएं
28. मैसर्स अरुनन इन्डस्ट्री नं. 134 पेक्क गुरी रंजयंत रोड, रामाप्पा नगर मद्रास-96 और इसका मद्रास-18 स्थित प्रशासनिक कार्यालय

धतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उर धारा 4 द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019/(179)/86-एन एन-2]

S.O. 4079.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M/s. Uma Industries, Board Mill Sithurajapuram (Via-Sivakasi)-626123.
2. M/s. R. N. Samy Bombay Dyeing Show Room, 302-303, Sathyamurthy Road, Arni-632301.
3. M/s. The Madras Telephones District, Staff Co-Operative Store Ltd., Telephone House, Madras-600001.
4. M/s. TPD-53, C. Sorppanandal Milk Producer, Co-Operative Society Ltd., C. Sorppanandal Chennagalm Taluk, N.A. Dist.
5. M/s. Alved Pharmaceuticals (P) Ltd. 5, Chandra Bagh Avenue, Dr. Radhakrishnan Road, Madras-4.
6. M/s. Ratnam Industries, 44/8, Poonamallee High Road, Madras-84.
7. M/s. The National Steel Fab. 125, 1st Floor, Eldams Road, Madras-18.
8. M/s. Industrial Engineers Service Division, 781, Annasalai, Madras-2.
9. M/s. K.V.R. Transports, No. 1, Vankata Ramiyer Street, Madras-600001.
10. M/s. Perfect Press Products, No. 16, Lake View Road, Madras-600033.
11. M/s. Metre Electrical Ind., 3/B1 Smith Lane, Mount Road, Madras-2.
12. M/s. Arbitech Polymerics Pvt. Ltd., L-5, SIDCO Indl. Estate, Villivakam Madras-49 including its Admn. Office at 15, Raja Ratnam St. Kulpauk, Madras-10.
13. M/s. United Farm Services No. 5 Krishnappa Maistry Street Woods Road, Madras-2, including its Admn. Office at No. 163, Kodambakkam High Road, Madras-34.
14. M/s. Krishna Enterprises, Abdul Razack Street, Saidanet, Madras-15, including its registered office at Madras-2.
15. M/s. Fuse Gear Electric Limited, Thandalam Village Striperumburdu Taluk, Chingleput Distt, including its Adm. office at No. 349, Poonamallee High Road, Aminjikarai Madras-29.
16. M/s. Moridian Pharmaceuticals (P) Ltd., Factory PP Amman Koil Street, Chrompet Madras-600044 including its Adm. office at Madras-43.
17. M/s. Vidvut Agni Furnace Components (P) Ltd., No. 5, SIDCO Indl. estate Madras-49 including its Admn. office at No. A13, 2nd Avenue, Anna Nagar Madras-40.
18. M/s. Chevro Leather, No. 232, N.S.C. Bose Road, Madras-1, including its Branch at 245 A&B, Chittaraupan Avenue, Calcutta-700006.
19. M/s. Kali Composite Metals 42/6-B Madras Road Melakaveri 612002, Kambakonam including its Show Room at 318, Mount Road, Teynampet Madras-18.
20. M/s. Southern Steel Industries, 205/2, G.S.T. Road, Ottery Village Vandalur, Madras-48 including its Admn. office at No. 2, Alandur, Madras-600016.
21. M/s. Tamilnadu Police Housing Corporation, Perlvar Building Madras including its branches at (i) Trichirapalli, (ii) Coimbatore and (iii) Palayamkottai.

22. M/s. The Swamimalisilk Handloom Weavers Co-operative Production & Sales Society Limited Thirumanjana Street, Swamimali-612302, including its showrooms at (1) Trichy, (2) Kumbakonam (3) Tribuvanam (4) Neyeveli.
23. M/s. We Two Match Industries, 8/139-C, Elayirampannai (Via-Sattur) including its Adm. office at 72, Javulikudai Street, Sivakasi-626123.
24. M/s. N. N. 36 Ramand District Fishermen Co-operative Federation Ltd., Valipattanam Post, Ramanathapuram including its branches at Thondi and Pomban.
25. M/s. Tiraj Enterprises, 5 Kamaraj Park Lane, Madras-13, including its Adm. office at 40, Pedariar Koll Street, Madras-600001.
26. M/s. Automotive Trader, 17, Begum Sahib 2nd Lane, Anna Salai, Madras-2, including its branch at Bangalore-560002.
27. M/s. The Kundrakudi Bharathi Industrial Co-operative Chlorate Factory Ltd., Kundrakudi-623206 including its branches at Sattur and Kovilapatti.
28. M/s. Arunn Industry, No. 134, Parungudi Panchayat Road, Ramappa Nagar, Madras, including its Adm. office at Madras-18.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(179)[86SS.II]

का.प्र. 4080 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स ए.यू. प्रिन्टर्स, भूपति विल्डिंग, विरुवनगर रोड सिवाकाशी
2. मैसर्स नैशनल हास्पिटल, 63 मल्लोड् स्ट्रीट, मद्रास-1
3. मैसर्स कुमारन सिक्यूरिटी ब्यूरो, प्लॉट नं. 2607, अन्नानगर, मद्रास-40
4. मैसर्स ए.बी. थामस एक्स्पॉर्ट लिमिटेड, नं. 59, बाला चारी रोड, मद्रास-32
5. मैसर्स मारथी एण्ड कम्पनी, 31 वेंकटाकृष्ण रोड, राजा अम्मापालापुरम मद्रास-28
6. मैसर्स एम.एम.पी.सी. इन्जिनियरिंग वर्क्स, मुरम्बई रोड, पञ्चेश्वराम टिकासी तालुक त्रिनेवली डिस्ट्रिक्ट मद्रास
7. मैसर्स रिलायन्स मेटल फिनिशर्स, 10 कालीमानपुरम स्ट्रीट मद्रास-2
8. मैसर्स इन्सैक्टो साइडम एण्ड इन्सैक्ट कैमिकल्स नैरवणपुरम, खेलवेरी रोड, मद्रास-2
9. मैसर्स श्री श्रीराबावर राव इन्जिनियरिंग कन्स्ट्रक्टर, 7 छठी रोड, बकला अत्तलम नगर, अदवार मद्रास-20
10. मैसर्स कस्सोलीडिटेड पुलेशन कन्ट्रोल, टाइप 2, 31 बी, एन.आई. स्टेट, तिरुवानमूर, मद्रास-41
1. मैसर्स श्री विजयालांज, मेन रोड वेदीनमाकानूर, मदुराई (कस्सा)

12. मैसर्स मैकनटाइल कम्प्यूटर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, फस्ट फ्लोर, साऊथ इन्डिया हाउस, 3840 अरिमेनियन स्ट्रीट मद्रास-1
13. मैसर्स एन आई ब्रिक वर्क्स, 65 मोनोस्टोव रोड, इमोर, मद्रास-8
14. मैसर्स श्री जमुना सिल्क नं. 135, लांग बाजार, वैतोर, एनए कस्बा
15. मैसर्स मैयूव कोरिया इन्जीनियरिंग कन्स्ट्रक्टर, 683 टी एच रोड, टोडोरपेट, मद्रास-81
16. मैसर्स इन्डियन ड्राइंग इन्स्यूमेंट इन्डस्ट्रीज नं. 2, मिटको स्टेट, मद्रास-98
17. मैसर्स एबीएन प्रोडक्शन्स नं. 38, अरकट रोड, बडालानी मद्रास-26
18. मैसर्स के.सी. कारपोरेशन मेन्टोर चैम्बर-21 एम सी निकोलर रोड, वेनपुर मद्रास-31
19. मैसर्स के.एम.एम.पी के मानाविषायम 4-1-8 ए चेयरमैन पी के एनए अरमुमा तदार रोड, सिवाकाशी
20. मैसर्स आर आर इलैक्ट्रोक्लस, 20 सैकिन्ड स्ट्रीट, गोपाला पुरम मद्रास-86
21. मैसर्स एम.बी के एम बांगारज एण्ड कम्पनी, राहस मिल 163-ए, कामराज सलाए, मदुराई-9
22. मैसर्स स्तो ग्राइड क्रीवर, 45-ए एम के पुरम, मेन रोड, मदुराई-11
23. मैसर्स पित्तवईमाल पेनर काटिंग वर्क्स, कोठानकुताम गांव (बाबा राजापालायम)
24. मैसर्स इन्डिया बूक डिस्ट्रीब्यूटर, 181 माऊट रोड, मद्रास 6
25. मैसर्स एसए जगन्नाथ एण्ड सन, नं. 2 रोड, मयनाडुपुर ए मद्रास-1
26. मैसर्स कृष्णा कंसल्टेंट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एण्ड कन्स्ट्रक्टर नं. 3 नन्दानाम एक्स्पेंडिन्स मद्रास-35
27. मैसर्स के मत्थाबालान, 20-ए कौकामाकुताम स्ट्रीट पेरी आयोप्पु मनासी, मद्रास 68
28. मैसर्स एम.ए. मेटल, वर्क्स, 188 सेडनडैमस रोड, चोलए, मद्रास-112
29. मैसर्स बैकटागपुरम मिल्क प्रोड्यूसर को-ओपरेटिव सोसाइटी, कवातूर एण्ड पोस्ट, अरकार तालुक एनए कस्बा
30. मैसर्स श्री थीवर ट्रांसपोर्ट, 385 निन्नी रोड, मेवूर मदुराई कस्बा
31. मैसर्स विजय इन्डस्ट्रीज एन-5, मिडको स्टेट काङ्गनागूर, मद्रास-51
32. मैसर्स जि नाचोमल पिलक प्रोड्यूसर का-ओपरेटिव सोसाइटी, मानमवाए, थुकापहेर्दे जेगम तालुक तार्थ अरकार कस्बा-9
33. मैसर्स आरजी कासी बार सॉ. नं. 19 ए. नं. 2 रोड, बम स्टेट्स मयनाडुपुराई
34. मैसर्स जे कोट इन्डस्ट्रीज अन्तामारजा नगर शकसकोएन रोड, राजापालायम-117
35. मैसर्स जय कृष्ण आफसेट प्रिन्टर्स 9/2, चेयरमैन, पी.के. एन.ए. असनूगा नगर रोड, सिवाकाशी

36. मैसर्स श्री गणेश भवन, रेलवे फीडर रोड प्लाता,

37. मैसर्स दिवस इन्डस्ट्रीज, 4-1-8ए, सेयरमैन पी.के.एस. ए.
अरुमुगा नगर रोड, शिवकाशी

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(180)/86-एस एस-2]

S.O. 4080.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. A. U. Printers, Boopathy Building, Virudhunagar Road, Sivakasi.
2. M/s. National Hospital, 63, Maunady Street, Madras-1.
3. M/s. Kumaran Security Bureau, Plot No. 2697, ANNA Nagar, Madras-40.
4. M/s. A. V. Thomas Exports Ltd. No. 59, Vallichari Road, Madras-32.
5. M/s. Sarathy & Company, 31, Venkatakrishna Road, Raja Annamalaipuram, Madras-28.
6. M/s. M.S.P.V. Engineering Works Surandai Road, Pavoorchatram (Tankasi Taluk Tirunelveli DT. Madras-
7. M/s. Reliable Metal Finishers 10, Kalimanpuram Street, Madras-2.
8. M/s. Insecticides & Allied Chemicals Narayana-puram, Vellachery, Road, Madras-601 302.
9. M/s. Shri D. Veerabhadra Rao, Engg. Contractor, 7 VI Road, Bakthavathslam Nagar, Adyar, Madras-20
10. M/s. Consolidated Pollution Controls, Ty-II, 31, V.S.I. Estate, Thiruvannmiyur, Madras-41.
11. M/s. Sri Vajaya Lodge, Main Road, Bodinayaka-nur, Madurai District.
12. M/s. Mercantile Computer Company Private Limited, First Floor South India House 36/40, Aremen-ian Street, Madras-1.
13. M/s. S.I. Brick Works 65, Montieth Road, Egmore, Madras-600008.
14. M/s. Sri Jamuna Silks, No. 135, Long Bazar, Vel-lore, N.A.D.E.
15. M/s. Manual Corrotya Engg. Contractor 683, T.H. Road, Tondiarpet, Madras-81.
16. M/s. Indian Drawing Equipment Industries No. 2, SIDCO Estate, Madras-98.
17. M/s. A.V.M. Productions, No. 30, Arcot Road, Vadapalani, Madras-600026.
18. M/s. K. C. Corporation, Mentmore Chamber, 21, M.C. Nicholar Road, Chetput, Madras-31.
19. K.S.S.P.K. Naachivayam 4-1-8-A, Chairman P.K.S.A. Arumuga Nadar Road, Sivakasi.
20. M/s. R. R. Electricals, 20, Second Street, Gupala-puram, Madras-86.
21. M/s. S.V.K.M. Thangaraj & Co., Rice Mill, 163-A, Kamraj Salai, Madurai-625 009.

22. M/s. Snow White Weleachars, 40A, M.K. Puram Main Road, Madurai-11.

23. M/s. Pitchaiammal Paper Cutting Works, Kothan-kulam Village (Via-Raja Palayam).

24. M/s. India Book Distributors, 681, Mount Road, Madras-600006.

25. M/s. S.A. Jagannathan and Sons, No. 2 Road, Mayi-laduthurai, Madras.

26. M/s. Krishna Consultants and structural Engineers Contractor, No. 3, Nandanam Extension, Mad-35.

27. M/s. K. Sathyabalan, 20-A, Chokkammakulam Street, Porinthoppu, Manali, Madras-68.

28. M/s. M.A. Metal Works, 188, Sydonhame Road, Choolai, Madras-112.

29. M/s. Venkatapuram Milk Producers Co-operative Society, Kavanur & Post, Arcot Taluk.

30. M/s. Sroo Thevar Transport 385, Trichy Road, Molur, Madurai District.

31. M/s. Vijay Industries, L-5, SIDCO Estate, Kodu-nagayr, Madras-600051.

32. M/s. CHE. Nachipattu Milk Producer Co-op. So-ciety, Manamlai, Thukkapettai, Changam Taluk, Arcot District.

33. M/s. R.G. Coffee Bar, No. 19-C, No. 2, Road, Bus Stand, Bayiladuthurai.

34. M/s. J-Cote Industries, Annamaraja Nagar, San-karankoil Road, Rajapalayam-626 117.

35. M/s. Jai Krishna Offset Printers, 9/2, Chairman, P.K.S.A. Arumuga Nadar Road, Sivakasi.

36. M/s. Sri Ganesh Bhavan, Railway Fodder Road, Palani.

37. M/s. Deviam Industries, 4-1-8A, Chairman P.K.S.A. Arumuga Nadar Road, Sivakasi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(180)/86-SS-II]

का.भा. 4081.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिये :-

1. मैसर्स श्री श्रीनियस, 30 बी बी कोएल स्ट्रीट, पेरियामैट मद्रास-3
2. मैसर्स कारी मंगलम को-प्रोपरेटिव लिमिटेड प्रोड्यूसर्स सोसाइटी लिमिटेड, कारी मंगलम बेगुम तास्वुक, एन ए कम्पा
3. मैसर्स सेलवान टैक्सराइलम नं. 10 पेरियामैट मद्रालाई स्ट्रीट, घरनामपट, गुक्षीमाताथ एन ए कम्पा
4. मैसर्स रॉक मैलिंग कम्पनी, 188, थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट मद्रास-1
5. मैसर्स महालक्ष्मी क्लब, 30 नार्थ भीम रोड, मद्रास-17
6. मैसर्स अम्बातूर श्री वेंकटरोवरा सहायनिधि लिमिटेड, सरय-नारायण, स्ट्रीट वेकटा पुरम अम्बातूर मद्रास-53

7. मैसर्स विलन सिम्यूरिटी थ्यूरो ए जै-45 ब्लॉक प्लॉट 2607 अन्नानगर मद्रास-40
8. मैसर्स तायून क्वाथ शाप-39 ईस्ट चित्रे स्ट्रीट, प्रथम मंजिन, मदुरई-1
9. मैसर्स सहहासी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड इम्प्लोईज को-प्रोविडेंट स्टोर्स लिमिटेड, नं० ई-2422 सेराकुप्पम वदालूर माडुल प्ररकट कस्बा
10. मैसर्स इन्डस्ट्रियल सिम्यूरिटी एण्ड इटैलीयेन नं. 10, शास्त्री स्ट्रीट शान्ति नगर, मानीग्राम मद्रास-93.
11. मैसर्स श्री वालोकानाथन सर्विस 5ए, एम.पी.के. एन स्ट्रीट चिदांबाराम
12. मैसर्स बाहुगानाथन टाकीज, चिदांबाराम, एम.ए. कस्बा
13. मैसर्स सोना टाकीज, चिदांबाराम, एम.ए. डिस्ट्रिक्ट
14. मैसर्स हिन्दुस्तान लुंगी कम्पनी नं. 10 पेरीअबु मडुरई स्ट्रीट धरनामपट, गुडीयत्तम, एन.ए. कस्बा
15. मैसर्स करन काडु एथीकनवरन सर्विस को-प्रोविडेंट सोसाइटी लिमिटेड, नं. के.वी. 76 करनकाडु पोस्ट कन्याकुमारी कस्बा
16. मैसर्स फतुमा एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग एन्टरप्राइजिज (फेम एडवरटाइजिंग) 5 बी-2 जे.पी. टावर, 7/2, नगाबाकम हाई रोड, मद्रास-34
17. मैसर्स न्यूजटुडे प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मेन रोड, युनाइटेड इन्डिया कालोनी, कोयामबाकम मद्रास-24
18. मैसर्स टासल इन्डस्ट्रियल स्टेट फार सेरोमिक, विरधाचम एम.ए. कस्बा
19. मैसर्स मोनाथी एण्ड कम्पनी, 186, धाम्बु चेट्टी रोड मद्रास-1
20. मैसर्स विद्यापितम, 36 मुबारक स्ट्रीट शोलींगूर-2
21. मैसर्स श्रीमेधा फीडिस एण्ड नूट्रीस (प्राइवेट) लिमिटेड, 985 टी.वी.एम. कालोनी, अन्नानगर, मद्रास-101 और इसकी चिगलपुर स्थित फैक्ट्री
22. मैसर्स प्रोडक्ट इन्जीनियरिंग डवलपमेन्ट प्लॉट नं. 93ए इन्डस्ट्रियल स्टेट, मद्रास-98 और इसका प्लॉट नं. 1618 अन्नानगर मद्रास-40 स्थित स्थानीय कार्यालय
23. मैसर्स धी वेन प्रेस, एम.पी.के.एन स्ट्रीट, चिदांबाराम
24. मैसर्स श्री मुग्गन सर्विस, 3ए एम.पी.के.एन स्ट्रीट चिदांबाराम-वरास
25. मैसर्स इन्डा इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज नं. 2, जी.ए.टी रोड, (लेन) अलन्दूर मद्रास-16
26. मैसर्स जिवुन अग्नि इन्जीनियरिंग प्रोडक्शन, ब्लाक ए-8 द्वितीय ऐवेन्यू, अन्ना नगर, मद्रास-2
27. मैसर्स बी प्रोरिएण्ड प्रोसेपरन 169-ई, मुन्नगनगर स्ट्रीट सिबाकाशी
28. मैसर्स एन फेनन फास्टेनर (प्राइवेट) लिमिटेड, 12/क, 12/5 बी, जी.एम.टी रोड, जिनगुड और हरली 118 धाडवे मद्रास-8 स्थित शाखा
29. मैसर्स मुल्लन एण्ड कम्पनी, लस्ती थिज एंटाकीज, चिदांबाराम
30. मैसर्स विलन (टैक्सटाइल) 12-13-14-अमान मन्नाधि मदुरई-1

31. मैसर्स प्रक्सोल कौगकल प्रोडक्ट, 51 मिटको इन्डस्ट्रीयल स्टेट, रानीपन, और इसकी प्रथम मन्जिन, 19 पेरीना मिस्ट्री स्ट्रीट, मद्रास-3 स्थित कलेक्शन कार्यालय

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उक्त धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थानों को लागू करनी है।

[एस-35019(181)/86-एम एस-2]

S.O. 4081.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. V. Srinivas, 30, V. V. Koil Street, Periamet, Madras-3.
2. M/s. Kariamangalam Cooperative Milk Producers Society Limited, Kariamangalam, Changam Taluk, N.A. District.
3. M/s. Solvan Textiles, No. 10, Periabba Mudali Street Dharanampet, Gudiyattam N.A. District.
4. M/s. Rock Belting Company, 106, Thambu Chetty Street, Madras-1.
5. M/s. Mahalakshmi Club, 30, North Boag Road, Madras-17.
6. M/s. Ambattur Sri Venkateswara Sahayanidhi Limited, Sath narayanan Street, Venkatapuram, Ambattur, Madras-53,
7. M/s. Vefan Security Bureau, AJ-45, Block (Plot 2607) Anna Nagar, Madras-40
8. M/s. Tayco Cloth Shop, 39, East Chitrai Street, 1st Floor, Madurai-1.
9. M/s. Seshasayee Industries, Limited, Employees Co-operative Stores Limited, No. E, 2422, Serakuppam Vadalur (South Arcot District).
10. M/s. Industrial Security and Intelligence No. 10 Sashtri Street Shanthi Nagar, Suligram, Madras-93.
11. M/s. Sri Vallikanathan Service, 5-A, S. P. Koil Street, Chidambaram.
12. M/s. Vaduganathan Talkies, Chidambaram, S.A. District.
13. M/s. Lena Talkies, Chidambaram, S.A. District.
14. M/s. Hindustan Lungi Company, No. 19, Periabba Mudali Street, Dharanampet Gudiyattam N.A. District.
15. M/s. Karankadu Agricultural Service Co-operative Society Limited, No. K.V. 76, Karankadu Post, Kanyakumari District.
16. M/s. Futura Advertising and Marketing Enterprises (Fame Advertising) 5, B-2, J.P. Tower, 7/2, Nangambakkam High Road, Madras-34.
17. M/s. News Today Printers and Publishers (Private) Limited, 1, First Main Road, United India Colony, Kodambakkam, Madras-24.
18. M/s. Tacel Industrial Estate for Ceramics, Vridhachalam, S.A. District.
19. M/s. Mecnakshi and Company, 186, Thambu Chetty Street, Madras-1.
20. M/s. Vidyapeetam, 36, Subba Rao Street, Sholinghur-2.

21. M/s. Omega Foods and Nutries (Private Limited, 985, TVS Colony, Anna Nagar, Madras-101, including its factory at Chingleput.
22. M/s. Product Engineering Development Plot No. 93-A, Industrial Estate, Madras-98, including its Regional Office at Plot No. 1648, Anna Nagar, Madras-40.
23. M/s. Sri Velan Press, S. P. Koil Street, Chidambaram.
24. M/s. Sri Murugan Service, 5-A, S.P. Koil Street Chidambaram.
25. M/s. Delta Engineering Industries, No. 2, G.S.T. Road (Lane) Alandur, Madras-16.
26. M/s. Vidyut Agni Engineering Products, Block-A-8, 2nd Avenue, Annanagar, Madras-2.
27. M/s. The Orient Processors, 169-E, Mundaga Nadar Street, Sivakashi.
28. M/s. Aero Fashion Fasteners (Private) Limited, 12/2, 12/5B, G.S.T. Road, Chingaleput, including its branch at 118, Broadway, Madras-8.
29. M/s. Murugan and Company, Lasse, Thailai Talkies, Chidambaram.
30. M/s. Milan (Textiles) 12-13-14, Amman Sannadhi, Madurai-1.
31. M/s. Aksol Chemical Products, 1, Sideo Industrial Estate, Ranipet, including its Collection Office at 1st Floor, 19, Periana Maistry Street, Madras-3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(181)86-SS-II]

का.ग्रा. 4082.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या हम बात पर सहमत होगी है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :

1. मैसर्स श्री न्यू डारिका लंच होम, मेन रोड, काकीनंदा
2. मैसर्स पदमानामा टाकिज, काकीनंदा
3. मैसर्स श्री एजेंसीज, गजामनरी स्ट्रीट हाऊस नं. 25-6-18 काकीनंदा
4. मैसर्स आई बी एम राजू इन्जिनियरिंग कान्ट्रेक्टर, 50-52-13 ए पी एण्ड टी कॉलोनी, विशाखापट्टनम
5. मैसर्स श्री माधवि टाहल फॅब्री, रामावरम (बाया) जगमपेटा
6. मैसर्स सत्या गौरी महस बल्पम भाई स्ट्रीट, काकीनंदा-7
7. मैसर्स कंगारू कोरुगेटर्स फॅब्री प्लॉट नं. 9/12 रोड नं. 6 आई डी ए, नाबाराम, हैदराबाद
8. मैसर्स आर आर मिन्नरल्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 48 ए एण्ड बी, आई डी ए, बेरनापल्ली, हैदराबाद-51
9. मैसर्स प्रहारा प्रिंटर्स 12-5-32/5 और 6 लालागेवा सिकन्नाबाद-17
10. मैसर्स मिडवेस्ट लिजिंग लिमिटेड, पुंजागुटा, हैदराबाद-82 और इसकी (1) कांग्रेस आफिस रोड गोवरपेट विजयवाडा (2) 14-11-14 प्रथम मंजिल द्वारकानगर विशाखापट्टनम (3) 105 सी मिन्सल टावर, नारीमन पाइन्ट, बम्बई स्थित तीन शाखाएं
11. मैसर्स स्टुकेवरा सी-7 इंडस्ट्रियल स्टेट, विशाखापट्टनम-7

12. मैसर्स विजय ट्रेडिंग कारपोरेशन डी नं. 27-32-93, 75 फीट रोड, विशाखापट्टनम
13. मैसर्स ए बी इंडस्ट्रीज रोड नं. 20 ए एण्ड बी, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स कुशाएगुडा, हैदराबाद-62
14. मैसर्स चन्द्रा एमरी स्टोन वर्क्स 2, 161, 11 रोड, न्यू टाउन अनंतपुर-1
15. मैसर्स मालसन पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 56 और 57 आई डी ए, गान्धीनगर, बालानगर हैदराबाद
16. मैसर्स इन्टेग्रेटेड जिओ इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, 12-13-120, स्ट्रीट नं. 3 तारानाका, हैदराबाद-17

यतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, को उा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(182)/86एसएस-2]

ए. के. भट्टारार्थ, प्रवर सचिव

S.O. 4082.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishment have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M/s. Sri New Dwaraka Lunch Home, Main Road, Kakinada.
2. M/s. Padmanabha Talkies, Kakinada.
3. M/s. Sree Agencies, Ganjamvari Street, House Number 25-6-18, Kakinada.
4. M/s. IVS Raju Engineering Contractor, 50-42-13 A, P & T Colony, Visakhapatnam.
5. M/s. Sri Maruthi Tile Factory, Ramavaram (Via) Jaggampeta.
6. M/s. Satya Gouri Mahal, Vallabhai, Street, Kakina-da-7.
7. M/s. Kangaroo Corrugators Factory, Plot No. 9/12, Road, No. 6 IDA Nacharam, Hyderabad.
8. M/s. R. R. Minerals and Chemicals Private Limited Plot No. 48 A & B, IDA, Choralapally, Hyderabad-51.
9. M/s. Arudhra Printers, 12-5-32/5 & 6, Lallaquda, Secundrabad-17.
10. M/s. Mid-West Leasing Limited, Punjagutta, Hyderabad, including its Branches at (1) Congress Office Road, Govarpet, Vijayawada (2) 14-11-14, 1st Floor, Dwarakanagar, Visakhapatnam (3) 105-C, Mittal Tower Nariman Point, Bombay.
11. M/s. Stru-Fabs, C-7, Industrial Estates, Visakhapatnam-7.
12. M/s. Vijai Trading Corporation, D. No. 27-32-93, 75 Feet Road, Visakhapatnam.
13. M/s. A. B. Industries, Shed No. 20, A & B, Electronic Complex, Kushaiguda, Hyderabad.
14. M/s. Chandra Emery Stone Works, 2-161, Hind Road, New Town, Anantapur-1.
15. M/s. Malson Paints and Chemicals Private Limited. Plot No. 56 and 57, IDA Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad.
16. M/s. Integrated Geo Instruments and Services Private Limited, 12-13-120 Street No. 3, Tarnaka, Hyderabad.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(1)82/86-SS.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

का.आ. 4083.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, विजया बैंक के प्रबन्धकों से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th November, 1986

S.O. 4083.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Vijaya Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1985.

BEFORE SHRI G. S. KALRA: PRESIDING OFFICER:
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL: NEW DELHI

I. D. No. 102/80

In the matter of dispute between :

Shri Lila Dhar Tamta,

s/o Shri Ram Lal Tamta,

r/o K-Block, 211, Dr. Ambedkar Nagar,
New Delhi.

Versus

The Regional Manager,
Vijaya Bank,
G-44, Connaught Circus,
New Delhi.

APPEARANCES :

Shri B. Gaur — for the workman.

Shri Uday Shetty — for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-12011/44/79-D.I.A. dated 20th September, 1980 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Vijaya Bank Limited in withdrawing the payment of driving allowance of Shri Lila Dhar Tamta, Peon-cum-Driver with effect from December, 1977 is legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?"

2. The case of the workman as put forth in the statement of claim is that he was appointed as a Peon in the respondent bank on 1-4-72 and subsequently he was assigned the job of Driver and he was re-designated as Driver-cum-Peon, in the month of June, 76. The Management vide its letter dated 10-3-77 also sanctioned the Driver's allowance of Rs. 52/- to the workman w.e.f. 10-6-77. Later the Management vide letter dated 26-11-77 transferred the workman to its Hauz Khas Branch and stopped paying him the Driver's allowance of Rs. 52/- from the month of December, 77. It is alleged that this action was taken by the Management with a view to victimise the workman for his Union activities.

Hence the workman has demanded that his designation may be restored as Driver-cum-Peon and he may also be paid Driver's allowance Rs. 52/- w.e.f. the date it was discontinued.

3. The Management in its written statement denied that the workman was at any time designated as Driver-cum-Peon or that he was posted to work as Driver-cum-Peon. However, it was stated that because of exigency of service the workman, who happened to know driving, was asked to drive the car belonging to the Management and for this purpose he was given Driver's allowance of Rs. 52/- PM. It was further stated that this arrangement was purely temporary and the workman was paid for the additional work done by him over and above his normal duties as Peon. It is further stated that since there was no requirement of a Driver at the Hauz Khas branch the workman was rightly not paid any Driver's allowance. It was also denied that this action was taken in order to victimise the workman for his Trade Union activities. Hence it was pleaded that the workman is not entitled to any restoration of his alleged posting as Driver-cum-Peon or to the Driver's allowance of Rs. 52/- PM.

4. Both the parties led the oral and documentary evidence in support of their respective cases and the case was fixed for arguments. However on 29-10-86 a settlement was arrived at and the Management agreed to grant the designation Driver-cum-Peon and also give Driver's allowance to the workman effective from that date provided the workman did not press for arrears for the past period. This offer was accepted by the workman. Hence the award is made to the effect that the workman shall be designated as Driver-cum-Peon and given Drivers allowance w.e.f. today and the workman shall not be entitled to any arrears for the past period. This reference is disposed of accordingly.

G. S. KALRA, Presiding Officer

Central Govt. Industrial Tribunal New Delhi.

October 29, 1986.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

October 29, 1986.

G. S. KALRA, Presiding Officer.

[No. L-12011/44/79-D.II(A)/D. IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

का.आ. 4084.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, रामाकृष्णा मैग्नेसाइट माईन्स, कोन्नाप्पानेक्कनपत्ती, सेलम (तमिलनाडु) के प्रबंधकों से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-11-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th November, 1986

S.O. 4084.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramakrishna Magnesite Mines, Kodeppanayakanpatti, Salem (Tamil Nadu) and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD, B.Sc. B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMIL NADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 29th day of October, 1986.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 42 OF 1986

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between

the workmen and the Management of Ramakrishna Magnesite Mines, Kondappanaickenpatti P.O., Salem-636008).

BETWEEN

The workmen represented by the President, District National General Workers Union, 69, Dr. Subbarayan Road, Salem-636001.

AND

The Proprietor, Ramakrishna Magnesite Mines, Kondappanaickenpatti P.O., Salem-636008.

REFERENCE :

Order No. 19(1)/86-Con. II/D. III(B), dated 10-6-1986 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference and other connected papers on record and upon hearing of Thiruvallargal A. Ashokan and M. R. Ravindra, Advocates appearing for the Management and the Union being absent, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workmen and the Management of Ramakrishna Magnesite Mines, Salem arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. 19(1)/86-Con. II/D.III(B), dated 10-6-1986 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

'Whether the action of the management of Ramakrishna Magnesite Mines, Kondappanaickenpatti, Salem in terminating the services of the 15 workmen listed below with effect from 24-8-1985 is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

1. Shri P. Jayaraman
2. Shri M. Ganapathi
3. Shri P. Ramu
4. Shri I. Govindan
5. Shri K. Kamalesan
6. Shri P. Palanisamy
7. Shri M. Subramani
8. Shri Backiam
9. Shri J. Chinnappillai
10. Shri K. Mariammal
11. Shri K. Chandra
12. Shri M. Kamala
13. Shri K. Madavi
14. Shri K. Ponnammal
15. Shri V. Chetu "

(2) Parties were served with summons for the hearing on 16-7-1986.

(3) On 16-7-1986, the Union was absent and no representation was made.

(4) Today, when the dispute was called, the Petitioner—Union was absent and not represented. No claim statement was received or filed. Management was represented by counsel. Hence the claim of the workmen is dismissed for default. No costs.

Dated, this 29th day of October, 1986.

Sd./-

INDUSTRIAL TRIBUNAL
THIRU FYZEE MAHMOOD, Presiding Officer
[No. 19(1)/86-Con. II/D. III(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1986

का.प्र. 4085.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ मयसूर के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रतिकारण, बंगलूर पंचाट को प्रकाशित करत है, जो केंद्रीय सरकार को 11-11-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th November, 1986

S.O. 4085.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Mysore and their workman, which was received by the Central Government on the 11th November, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE.

Dated this the 27th day of October, 1986

Central Reference No. 3 of 1981

I PARTY

S.M. Kodanarama Reddy,
C/o. K. Ramaiah, 113,
Srinivasa Nagar,
Banashankri I Stage,
II Block, Bangalore-50.

II PARTY

The Chairman & Managing
Director, State Bank of
Mysore, Head Office,
Bangalore-560009.

APPEARANCES :

For the I Party : Shri T. N. Raghupathy, Advocate, B'lore.

For the II Party : Shri C. M. Nagabhushana, Advocate, Bangalore.

REFERENCE

(Government Order No. L-12012(37)/80-D.II.A
date 23-2-81)

AWARD

The Central Government after forming an opinion that an industrial dispute exists between the above parties has referred this dispute for adjudication in exercising the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on the following Schedule :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Mysore, Bangalore in dismissing Shri S. M. Kodandarama Reddy, Ex-Head Cashier with effect from 19-8-1976 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. After the reference, the parties have filed their respective statements. Since it was incumbent on the part of this Tribunal to give a finding on the validity of Domestic Enquiry that issue was taken as a preliminary issue. After recording the evidence on this issue, this Tribunal gave a finding on 6-12-85 that the domestic enquiry conducted by the II Party on the misconduct was fair and proper. Thereafter the parties have been directed to address their arguments on the merits of this dispute. Since the validity of domestic enquiry was held in favour of the management, the counsel for the I Party workman has been directed to show any perversity in the findings of the enquiry officer and also victimisation or

unfair labour practice. Accordingly the learned counsels have addressed their respective arguments without resorting to any further evidence on this matter.

3. Before adverting to decide this case on its merits, it is necessary to note the pleadings of the parties on these points.

4. The I Party has contended that the order of dismissal is the out come of malafides, as certain officials who did not like the I Party were behind the initiation of disciplinary proceedings. The II Party is guilty of unfair labour practice in having victimised the I Party. The enquiry officer had no competence, therefore the order of dismissal is vitiated. None of the charges were true nor they have been proved. The findings of the enquiry officer is perverse.

5. The I Party further contended that he could not undertake the journey for which he has obtained an advance of Rs. 600/- due to illness of his wife and further he had also felt ill after sometime. With regard to the charge of shortages the I Party has contended that in the very nature of the job, the shortage would occur and he had agreed to make good both the shortages. With regard to state of drunkenness he has denied the whole allegations and the enquiry officer was committed an error in coming to a conclusion that this charge was proved. The punishment meted out is out of all proportion to the alleged misconduct in view of the honest service rendered by the I Party for nearly 17 years without any blemish.

6. The II Party in their counter statement have denied all the averments made by the I Party workman and further contended that the I Party who drew the amounts for purchase of tickets on 6-9-75, did not produce the tickets by 8-9-75 as undertaken by him nor he has informed the bank that he is not availing leave for concession facility. After the II Party issued a notice, he came up with a plea that he was not undertaken the journey due to the illness of his wife and himself. The I Party after joining the duty has written a letter which is an afterthought to cover up his illegal act.

7. It is further contended that he was found short of the amounts shown in the charge sheet and further he was found in state of drunkenness when he attended the Bank and all these acts are grave misconducts and the II Party rightly initiated the disciplinary proceedings and the enquiry officer who conducted this enquiry gave a correct finding on the materials placed before him. Hence the dismissal of the workman is justified in the interest of the Banking Institution.

8. Now the points that arises for determination are :

1. Whether the I Party proved that the findings of the enquiry officer is perverse and his dismissal amounts to victimisation and unfair labour practice?
2. Whether the order of dismissal is disproportionate to the misconduct alleged against the I Party workman?
3. What order?

9. FINDINGS :

Point No. 1—negative.

Point No. 2—negative.

Point No. 3—as per order below.

10. REASONS :

Point No. 1 :—The specific charges made against this workman is to be found in the charge sheet dated 4-3-76 which has been marked as P. Ex. 1 in the domestic enquiry. Earlier to this charge sheet two show cause notices were issued, one on 6-11-75 and another dated 26-12-85 which have been marked in the enquiry as P. Ex. 6 and P. Ex. 7 respectively. After the workman gave his reply to the show cause notices a regular charge sheet was issued alleging the following acts of omissions and commissions by the I Party :

“You availed an advance of Rs. 600/- on 6-9-75 to enable you to purchase 4-1/2 railway tickets for your intended journey alongwith the members of your family from Bangalore to Goa via Gokarna

and back under ‘LEAVE FARE CONCESSION’. You undertook to produce 4-1/2 tickets/money receipts before your departure i.e. before 8th September 1975. You have failed to produce the relative tickets/money receipts nor refunded the amount taken by you as advance before 8th September 1975 i.e., the date from which you were supposed to be on leave under leave fare concession.

You have also failed to prefer any leave fare concession bill duly enclosing the relative receipts subsequently even though you reported back to duty on 3-10-75.

Your aforesaid act is deemed as prejudicial to the interests of the Bank and you are charged with committing a Gross Misconduct in terms of para 19.5(j) of the First Bipartite Settlement.

2. (a) A shortage of Rs. 70/- in coins of 50 paise denomination was noticed by the Accountant of the Branch who is the joint custodian while verifying the branch cash balance on 16-12-1975.

(b) On 17-12-1975, you left the premises of the Branch leaving the keys of the currency chest without obtaining the sanction of the leave and without properly handing over charge of the cash and keys to the cashier designated by the Manager. Subsequently, when the cash was verified in the presence of the Accountant and other cashiers, a shortage of Rs. 80/- was noticed in the denomination of Rs. 20/- in your hand balance.

Your aforesaid acts are prejudicial to the interests of the First Bipartite Settlement, an act of Gross Misconduct in terms of para 19.5(j) of the First Bipartite Settlement.

On 17-12-1975, you attended the office in a state of drunkenness which is deemed as an act of Gross Misconduct in terms of para 19.5(c) the First Bipartite Settlement.”

11. To prove the above said charges the II Party have examined Mr. Govinda Setti, Manager of the Bank, Mr. Sreenivasa Murthy, Accountant, Mr. Rajeevalochana, Cashier, Godown-keeper and Mr. Prabhakar, Cashier/Clerk. The workman appears to have not examined any witnesses and after receiving summing up reports by the prosecution and the defence, the enquiry officer has gave his findings that the workman was found guilty of all the charges except charge No. 3(b)(1).

12. The learned counsel for the I Party Shri T. N. Raghu-pathy has submitted that with regard to the first charge of non-performing journey after availing an advance for that purpose, was beyond the control of the I Party workman due to the fact his wife and subsequently the workman fell sick during that period and with regard to the shortages of amounts found on Rs. 70/- on 16-12-75 and Rs. 80/- on 17-12-75, such shortages was inevitable and with regard to state of drunkenness, the same has not been proved, hence the report of the enquiry officer is nothing but perverse. The learned counsel further submitted that no deliberate intention was made against the workman for the omissions and commissions, hence the charge is defective. When once the workman accepted the responsibility and expressed his disability such acceptance does not lead to a conclusion of misconduct for negligence on the part of the workman.

13. Against this submission the learned counsel for the II Party Sri C. M. Magabhusan, while supporting the findings of the enquiry officer, has contended that this workman after taking advance on 6-9-75 has not shown the tickets on 8-9-75 nor made any communication to the Bank even when he joined the duty on 3-10-75 and he has not made any efforts to explain the reason for not undertaking the journey as a normal or reasonable man but he writes a letter only on 30-10-75 when he has smelled that an action will be taken against him. The learned counsel further submitted with regard to the shortage of Rs. 70/- the workman has not informed this shortage but it was detected when Mr. Sreenivasa Murthy verified the accounts and hence it cannot be

said that the shortage has been occurred in the course of the business. The learned counsel further submitted with regard to the shortage of Rs. 80/- which was deducted immediately after he has taken the leave on 17-12-85 and he has accepted this shortage also. The counsel further submitted with regard to the allegations of drunkenness except denying this workman has not given any explanation what-so-ever and this Tribunal has to take judicial notice under Section 56 of the Evidence Act and further he has not cross-examined two witnesses who have made specific allegations. The learned counsel further submitted since the two witnesses on the charge of drunkenness have given an evasive evidence, the enquiry officer has relied on the evidence of another witness and such a course cannot be called as a perverse approach to come to a conclusion against the workman. He has further submitted that the acts of omissions and commissions committed by this workman has made the Bank to lose complete confidence on him, hence he has not entitled for any relief from this Tribunal.

14. This workman has been charged for a gross misconduct under clauses 19.5(j) of I, II and III Bipartite Settlements. According to sub-clause (j) "doing any act prejudicial to the interest of the Bank or gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss".

15. With regard to Act of victimisation and unfair Labour practice on the part of the II arty, the I Party has not placed any material either before the Enquiry or before this Tribunal. Hence, this allegation remains as mere allegation without any proof.

16. Now coming to the fact of perversity, since no independent evidence has been adduced before this Tribunal, it is necessary to look into the evidence adduced in the domestic enquiry. As rightly submitted by the learned counsel for the II Party, this Tribunal has to find out the perversity in the report of the enquiry officer on the available evidence on record, whether any reasonable man can come to a conclusion of what arrived at by the enquiry officer on the available evidence.

17. With regard to the first charge of availing an advance and not undertaking a journey, the said act has not been seriously disputed by the workman. His defence is that due to illness of his wife and later his ill health, prevented him to undertake the journey and on 30-10-75 he has brought this fact to the notice of the Manager and requesting thereon to deduct this amount from his monthly salary, this letter is marked as Ext. W-3 and as P. Ex. 9 in the domestic enquiry.

18. On this point one Mr. Govinda Setty, the Manager of that Branch was examined and he has stated in his evidence that this workman has received an advance of Rs. 600/- on 6-9-75 for leave fare concession and after reported back for duty on 3-10-75 has gave a letter on 30-10-75 explaining thereon why he has not undertaken the journey and for the deduction of that amount in his salary. It is also come in the evidence that it was incumbent on the part of the workman to show the railway tickets before 8-9-75 which was not done by this workman. He has also further stated that except remittance of Rs. 290/- on 31-1-76 the workman has not made good the amounts received by him for this purpose, though he has received the regular salaries for the months of September, October, November and December. In the cross-examination of this witness the above facts has not been disputed.

19. On the basis of this evidence, the enquiry officer has come to the conclusion that since the employee has not intimated to the branch that he could not perform the journey immediately due to illness but waited for a show cause notice from the branch to come with the explanation that he and his wife were laid-down sick, is exclusively established that the employee has failed to produce the relative tickets/money receipts nor refunded the amount in full taken by him as advance under leave fare concession.

20. The workman has produced a medical certificate dated 1-10-75 before this Tribunal which is marked as Ext. W-1 to prove that he was medically unfit from 8-9-75 to 1-10-75.

According to this certificate, this workman was in possession of this certificate on 1-10-75 itself but the same was not produced before the enquiry officer. Added to this he has not examined the Doctor nor made any communication upto 30-10-75 regarding his illness and illness of his wife, the enquiry officer has rightly come to a conclusion that this workman has misused the advance amount granted to him for a purpose other than for what it was intended to. Hence I find no perversity in the findings of the enquiry officer on this charge.

21. Now come to the shortages of Rs. 70/- of 0.50 paise denomination and Rs. 80/- of four pieces of Rs. 20/- denomination notes, which alleged to have been found on 16-12-75 and 17-12-75, the Manager has stated that the second witness Mr. K.L. Sreenivasa Murthy, Accountant has reported the shortage of Rs. 70/- in the hand balance held by the acting Head Cashier Mr. Kodandarama Reddy vide his letter dated 16-12-75 which was marked as P. Ex. II in the enquiry. This was corroborated by Mr. K. L. Sreenivasa Murthy. Mr. Sreenivasa Murthy was further stated that on 17-12-75 when this workman applied for a leave on that day, chest balance was verified and there was shortage of Rs. 80/- of Rs. 20/- denomination. This fact was corroborated by the third witness Sri Rajeevalochana in his evidence. It is also in the evidence that this workman was undertaken to pay those shortages after it was brought to his notice.

22. This witness have been cross-examined by the defence representative at a stretch after their examination-in-chief. It is elicited in the cross-examination of Mr. K. L. Sreenivasa Murthy that Rs. 70/- shortage was detected after he found that there was an alteration of figures to Rs. 87.50 from Rs. 17.50 in 0.50 paise denomination in the changes reduced on 15th December 1975. It is also elicited that the bonafides of this workman was suspected due to his appearance in the office on 17-12-75 and again the shortage of Rs. 80/- was found in the hand balance of this workman. In the written submissions of this workman, he has accepted the responsibility for the shortage of Rs. 70/- and with regard to shortage of Rs. 80 he requested for a joint responsibility of Mr. K. L. Sreenivasa Murthy, who received the charge of cashier on 17-12-75.

23. The enquiry officer relaying on the admission for the shortage of Rs. 70/- and relaying on the evidence of second and third witness for the shortage of Rs. 80/- has held that his workman was responsible for these shortages and these charges have been proved.

24. The learned counsel for the workman has submitted with regard to shortage of Rs. 70/- that for a person who is working as a cashier such shortages are bound to occur-hence the same cannot be held as a misconduct on the basis of the duty and responsibility entrusted to a cashier. Against this submission, the learned counsel for the Bank has submitted that this act of shortage is a deliberate act done by the workman as he has failed to inform the shortage before it was detected and further there cannot be any change for a shortage of 140 Nos. of 0.50 paise coins in the usual transactions.

25. There is some considerable force in the submission of the learned counsel as the responsibility was accepted by the workman only after it was detected by the second witness and hence I find no reason to interfere with the findings of the enquiry officer on this charge.

26. Now coming to the shortage of Rs. 80/- that this shortage being found in the Head Cashiers Hand Balance as per the evidence of Mr. Rajeevalochana the findings of the enquiry officer on this charge cannot be called as perverse order.

27. Now coming to the charge of drunkenness on 17-12-75 initially three witnesses have gave their statement on this charge. The reason attributed by this witnesses are that there was a foulsmell coming from the mouth of this workman and he was slur in his talk and he was also unsteady

and his eyes were red. On this charge though the evidence was a little bit shakky, the witnesses were only stated the physical condition of this workman when he came to the Bank on 17-12-75. But however the evidence on this point is very consistent by Mr. Sreenivasa Murthy, Accountant who was also present at that time. This witness, as an ordinary human being, was stated his impressions of a drunkenman at page No. 4 of his cross-examination. There is absolutely no evidence of any suggestion by the defence that this witness is giving a false evidence to implicate this workman due to enmity or for any reason. There is not even a suggestion by the defence that he is giving a false evidence only to injure the reputation of this workman. Added to this, this workman has not explained in his explanation to this charge except denying the charge in toto. Taking into consideration the sequence of event that was alleged against this workman the enquiry officer has come to a conclusion of finding of guilt of the charges levelled against him as an ordinary prudent men. Though there is scope for this Tribunal to come to a different conclusion on this point, for lack of medical examination, to find out the drunkenness, it should not be forgotten that this workman after attending the Bank on 17-12-75 immediately applied for a leave and went away from the Bank. To appreciate the reasonings of an enquiry officer in a domestic enquiry the ordinary and natural sequences should be taken into consideration and not a proof that is wanted in proving a criminal case. Hence I hold this point in the negative.

28. Point No. 2 : The punishment for gross-misconduct under clauses 19.6 of Bipartite Settlements may be dismissed without notice, warning, fine and a discharge.

29. On this point the learned counsel for the II Jarty has admitted that due to the misconducts of the nature committed by this workman the Bank has lost confidence and the proved misconducts are being grave in nature, this Tribunal should not interfere with the order of dismissal which is not disproportionate to the misconduct committed by this workman. The learned counsel further submitted that since this workman has committed latches in raising this dispute after a period of 4 to 5 years from the date of his dismissal, any alteration in the order of dismissal will seriously affect the II Party Institution.

30. Under Section 11-A, this Tribunal has got jurisdiction to set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions. If any, as it thinks fit or to give some other relief to the workman including award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may required. For such modifications the Tribunal shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidence in relation to the matter.

31. If we scrutinise the case in the back-ground of the limitations shown in Section 11-A of the Act, this is a case where this workman has indulged in committing a serious of misconducts from the date he obtained the advance for leave fare concession. He also neglected to make good of the amounts received by him in subsequent months and further indulged in the acts of committing shortages in the amounts entrusted to him. The II Pary Bank after observing a seriousness of the misconducts committed by this workman has ultimately issued a charge sheet and conducted the domestic enquiry. The evidence placed in the domestic enquiry was cogent, consistent and corroborative. In view of these material this Tribunal find no reason to apply the benefit of Section 11-A of the Act and hence the order of punishment is not disproportionate to the misconduct committed by this workman. Hence I hold this point also in the negative.

1157 GI/86—9

AWARD

The II Pary management are justified in dismissing the services of this workman on approved misconduct and the workman is not entitled for any relief.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by her and corrected by me.)

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-12012/37/80-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1986

का.डा. 4086:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुकरण में, केंद्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कामदारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2 बनारस के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 10 नवम्बर 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th November, 1986

S.O. 4086.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 143 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Muzaffarpur and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri B. Lal, Advocate, and Shri D. K. Verma, Advocate.

On behalf of the employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate and Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Insurance.

Dated, Dhanbad, the 31st October, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-17012/30/85-D.IV(A), dated, the 10th October, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Muzaffarpur in dismissing Shri R. P. Yadav, Assistant in the Divisional Office, Muzaffarpur with effect from 19-5-81 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

The case of the management is that the concerned workman Shri R. P. Yadav was appointed as an Assistant on 23-11-57 and was posted at Muzaffarpur Divisional Office to work under the Divisional Manager. While performing his duties as Asstt. in the Accounts department of Muzaffarpur Divisional Office, the concerned workman committed

a serious misconduct for which chargesheets were issued to him. The concerned workman was holding LIC policy No. 10258658 in his own name which lapsed in July, 1968 on account of non-payment of yearly premiums due on 9-7-68. He applied for revival of his above lapsed policy in Form No. 460 by filling the details on 22-9-69. Question No. 5 of Form No. 460 requires mention of the payment of arrears of premium and as such the concerned workman filled up that question indicating that he deposited arrears of premium of Rs. 530 on 3-8-68 by D.O.C. No. 90824, Rs. 800 on 5-9-68 by D.O.C. No. 1151, Rs. 1000 on 21-8-69 by D.O.C. No. 660, Rs. 943 on 26-8-69 by D.O.C. No. 685 and Rs. on 22-9-69 by D.O.C. No. 799. It was subsequently discovered that the concerned workman had actually deposited Rs. 25 on 22-9-69 by D.O.C. No. 799 only and that the other deposits purported to have been made on other dates through above D.O.C.'s were found to be false and thus he misled the management to revive his lapsed policy by making false entries in Form No. 460 and cheated the corporation by dishonest means adopted by him while working in the accounts department of the divisional office Muzaffarpur. It was subsequently found that Rs. 530 deposited on 3-8-68 pertained to policy No. 10226975 on the life of Smt. R. S. Devi. The amount of Rs. 800 deposited through D.O.C. No. 1151 on 13-9-68 (and not on 5-9-68) was against policy No. 70749854 received from Gauhati Divisional Office Cheque No. 020413 drawn on U.B.I. Gauhati. The deposit of Rs. 1000 deposited on 21-8-69 was against policy No. 29433876 on the life of Shri B. Singh and the amount of Rs. 943.75P. (not Rs. 943) deposited on 26-8-69 through D.O.C. No. 685 was relating to policy No. 29522183 on the life of Shri C Singh. The concerned workman taking the advantage his posting in the accounts department got his Form No. 460 processed and filled in Form No. 3423 and Form No. 3456 on 22-9-69 himself and obtained the signature of Shri S. S. Jha dealing Assistant on those forms and he himself put his signature on Form No. 3456 in the capacity of dealing Assistant of accounts department and adjusted the amount in adjustment book which was being maintained by him. The concerned workman obtained the signature of his colleague Shri S. S. Jha on Form No. 3423 and Form No. 3456 on misrepresentation of facts and using his friendship with Shri S. S. Jha who signed the same in good faith. It was the duty of the concerned workman to verify form No. 3456 before putting his initial on the said form regarding the amount mentioned against D.O.C.'s with reference to the relevant account books. It was also his duty to examine original deposits before writing the adjustment register and to satisfy himself with the details contained in Form No. 3456 were true with reference to original deposits. The concerned workman thus committed fraud dishonesty misrepresentation while filling up Form No. 460 in the capacity of policy holder, Form No. 3456 and 3423 in the capacity of an Assistant and he also committed breach of his duty in the capacity of an Assistant of the accounts department in omitting to examine the original deposits before making adjustment in the adjustment register. The concerned workman indulged in fraud and dishonesty taking advantage of his posting in the accounts department and got his policy revised retrospectively and there his original policy No. 10258658 continued from the date of commencement. After discovery of the above facts the concerned workman was issued with the chargesheet dated 25-2-75 containing the full facts constituting the misconduct fraud and dishonesty in connection with employers business.

The concerned workman persuaded Shri Ramnakhhi Lal his co-villager to part with his policy No. 10256957 being the joint policy of Shri Ramnakhhi Lal and his wife Shvama Devi for getting their age admitted in the policy bond. The concerned workman submitted his explanation for grant of loan on behalf of Shri Ramnakhhi Lal and his wife Form No. 3419 was filled up on 24-8-68 by the concerned workman. It was processed and an amount of Rs. 2400 was assessed as loan to be paid to the applicant after getting the bond deposited in the office. The concerned workman deposited the said policy bond along with the loan bond for Rs. 2400. The loan bond containing purported

authorisation of the policy holders permitting him to receive the loan on their behalf. On the strength of the loan bond purported to have been signed by the policy holders, the concerned workman received the amount of Rs. 2400 as loan advanced against policy No. 10256957 of Shri R. P. Lal and his wife. The concerned workman deposited cheque drawn in favour of the corporation for Rs. 1259.75P. towards repayment of the loan and interest taken against policy No. 10256957 of Shri R. P. Lal and his wife. The concerned workman filled up the adjustment voucher in Form No. 3423 and Sundry receipt in Form No. 3456 for Rs. 1259.75P. on the basis of cheque deposited by him and obtained the initial of Shri N. K. Thakur dealing assistant and thereafter the concerned workman changed No. 1 to 2 making the amount of Rs. 1259.75P. to Rs. 2259.75P. both the adjustment vouchers and Sundry receipts. Thus he adjusted the loan to the extent of Rs. 2259.75P. and the balance amount of Rs. 426.61P. remained outstanding. (The loan was for Rs. 2400 plus the interest accruing on it during the intervening period Rs. 286.36P. = Rs. 2686.36P. The receipts purported to have deposited Rs. 2000 as principal out of Rs. 2400 and Rs. 259.75P. as interest out of the interest of Rs. 286.36P. Thus the balance remained Rs. 400 as principal and Rs. 26.61P. as interest. The concerned workman obtained the signature of the dealing Assistant Shri N. K. Thakur on the adjustment voucher and Sundry receipt on 26-8-70. The cashier however detected that there was a discrepancy in the cheque and returned the cheque to the concerned workman and took back the cheque deposit receipt. The entry was penned through containing the cheque receipt in the cash book. The concerned workman presented an application purported to be of Ramnakhhi Lal and his wife for grant of second loan which was processed on 4-9-70. The said application contained the endorsement of the concerned workman with back date on 28-7-70. The concerned workman filled up Form No. 3519 on 4-9-70 and got the same processed for a loan of Rs. 3400. The concerned workman submitted the loan bond on 17-9-70 along with the authorities purporting to be of Shri R. P. Lal and his wife authorising the concerned workman to withdraw the amount of Rs. 3400. On the strength of the said loan bond the payment voucher in Form No. 3427 was prepared for Rs. 3400 by the concerned workman and out of the amount of the said Rs. 3400 the concerned workman adjusted the balance amount of Rs. 426.61P due against the previous loan and the amount of Rs. 2973.39P. was received by the concerned workman against policy No. 10256957 of Shri R. P. Lal and his wife. The concerned workman misused his posting as Assistant in the accounts department and manipulated things in a pre-planned way and cheated the corporation of Rs. 2259.75P. at the first instance and forged the signature of Shri R. P. Lal and the LTI of his wife and the attestation certificate purported to be of S.D.O. on the loan bond and obtained the subsequent loan of Rs. 3400 from the corporation. The concerned workman was issued with a chargesheet dated 22-4-75 containing the aforesaid detailed facts constituting the misconduct of dishonesty, fraud in connection with employers business.

The concerned workman did not submit his reply to the above two chargesheets dated 25-2-75 and 22-4-75 and went on avoiding to reply to the chargesheets on some plea or the other with a view to avoid disciplinary action. The management appointed Shri N. Pradhan the then Assistant Divisional Manager Muzaffarpur to enquire into the charges dated 25-2-75 and 22-4-75. The enquiry was delayed for about 4 years on account of several dilatory tactics adopted by the concerned workman. Subsequently the enquiry was held in presence of the chargesheeted workman who fully participated in the enquiry and cross-examined the management's witnesses and also produced his own defence witness. A departmental enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice and in accordance with the staff regulation 1960 of LIC. The concerned workman was allowed to peruse all the relevant documents filed by the management and to adduce his own defence witness and he was also given copies of the documents relied upon by the management. There had been no violation of the principles

of natural justice in holding the enquiry against the concerned workman. After completing the enquiry the enquiry officer submitted his enquiry report dated 2-6-79 on the basis of the materials on the record of the enquiry proceeding holding the concerned workman guilty of the charges of misconduct levelled against him. The competent authority considered the enquiry report, the enquiry proceedings together with the exhibits and all other relevant papers and thereafter he proposed to impose penalty of dismissal of the concerned workman and issued a show cause notice to him. The Divisional Manager who was the competent authority issued the show cause notice dated 11-10-80 against the proposed punishment and thereafter the concerned workman submitted his reply which was found to be unsatisfactory. There was no extenuating ground to impose lighter punishment than dismissal and as such the competent authority issued the order of dismissal dated 19-5-81.

The case of the concerned workman Shri R. P. Yadav is that he was appointed as an Assistant and was posted at Muzaffarpur Divisional Office by the Zonal Manager Zonal office, Calcutta as per his letter dated 22-11-57. The concerned workman was assigned the accounts department within Muzaffarpur Divisional Office of the Corporation. The condition of service including disciplinary matter of the employees of the Corporation are covered by the LIC (staff) Regulations, 1960. According to the regulations as it stood at the relevant time no order of dismissal could be passed against the concerned workman by any authority other than the appointing authority. His appointing authority was Zonal Manager but was dismissed from service by the Divisional Manager Muzaffarpur and as such the dismissal order was bad.

The concerned workman while working as an Assistant in Zonal Divisional Office of the corporation took a LIC policy No. 10258658 from 9-7-1961 on yearly premium. His policy lapsed due to non-payment of the premium but he got it subsequently revived by the depositing the amount of due premium. The concerned workman was told on enquiry that the entire due premium with interest thereon upto date was to be paid by the concerned workman and that he was still to deposit a sum of Rs. 25. On 22-9-69 the concerned workman deposited the said amount and completed form No. 460 as required by the rules which was accepted after proper verification by the then A. O. (PHS) Shri A. K. Sarkar and it was passed by the then A.D.M. Shri P. C. Mahanty. After completing all the formalities, the concerned workman was issued duly stamped sundry receipt No. 4898. There was some hostile element in the divisional office unfavourably disposed towards the concerned workman and under then instigation, the Divisional Manager framed a chargesheet dated 20-4-71 against the concerned workman alleging that the concerned workman had knowingly acted in a manner highly detrimental to the interest of the corporation which proved would make him liable for appointment under Regulation 39 of the staff regulations 1960. It was stated in the said chargesheet that the amount noted in the adjustment came to Rs. 3298 but in fact only Rs. 25 was deposited by the concerned workman and all other deposits brought under adjustment related to other policy holders which amounted to making false statement. It was also alleged that the concerned workman had committed irregularities with regard to the preparation of sundry receipt. The concerned workman denied the charges. In order to effectively submit the explanation and in order to establish his innocence the concerned workman prayed for the necessary documents to be furnished to him but those documents were never made available to him which seriously handicapped his defence. Another chargesheet was framed against the concerned workman dated 13-9-72 alleging false and fictitious payment by the concerned workman in relation to join life policy bond No. 10256957. In this respect also the concerned workman prayed for the necessary documents from the Divisional Manager for giving proper explanation but this was not complied. Subsequently the enquiry was set up into the charges and the concerned workman was dismissed from service by order of the

Divisional manager dated 18-12-73. As the adjudication proceeding was pending at that time before the National Industrial Tribunal, Jabalpur an application was filed by the corporation before the said Tribunal under Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act for approval of the order of dismissal of the concerned workman. After hearing the parties and giving elaborate consideration to the materials and evidence brought on record on behalf of the parties, the National Industrial Tribunal, Jabalpur came to the conclusion that proper opportunity was not afforded to the concerned workman and the principles of natural justice were flouted by the authorities of the corporation in as much as documents which the concerned workman wanted for the defence was denied to him. The National Industrial Tribunal after elaborately considering the merits of the respective parties rejected the case of the management and refused to give approval to the action of the corporation in dismissing the concerned workman from his service and a direction was made that the concerned workman be reinstated in service with effect from the date of his suspension. The said order was not challenged by the corporation before any higher Court and the order became final and it was also implemented by the management resulting reinstatement of the concerned workman. The concerned workman cannot again be charged and punished for the same offence in respect of which the National Industrial Tribunal already decided, and as such the management was not justified in submitting a fresh chargesheet dated 25-2-75 against the concerned workman.

The management drew up another chargesheet dated 22-4-75 in regard to the allegations covered by the earlier chargesheet dated 13-9-72 with minor alterations but in essence the allegations were the same. The concerned workman submitted before the D.M. that it was not open in law or otherwise to reopen the matter covered by the chargesheet dated 20-4-71 in view of the judgement and order of the National Industrial Tribunal and to reframe chargesheet dated 25-2-75. According to the concerned workman the earlier chargesheet dt. 13-9-72 had been dropped when the concerned workman demanded copies of the relevant document and it was not persuaded thereafter. The concerned workman requested the management to supply the copies and necessary and relevant documents to enable him to submit his explanation vide several letters but the copies of the relevant documents were not supplied to him. The Divisional Manager neither showed the relevant papers nor supplied copies therefore. The Divisional Manager appointed Shri N. Pradhan, Asstt. Divisional Manager as Enquiry Officer who was directly subordinate to him. The concerned workman had filed objections before the Divisional Manager that the enquiry officer was neither competent to hold the enquiry nor he was conducting the enquiry in accordance with the principles of natural justice and requested for appointment of an impartial enquiry officer but his prayer was rejected. His appeal against the said order was also rejected by the Zonal Manager. The enquiry officer had conducted the enquiry against the principles of natural justice. The enquiry was a pre-determined one and was an empty formality to bring home the charges against the concerned workman. The enquiry Officer had not allowed him to be represented through a lawyer. The enquiry officer did not afford reasonable opportunity to the concerned workman to defend him. After the submission of the enquiry report to the Divisional Manager by the Enquiry Officer on 2-6-79, the Divisional Manager asked the concerned workman to show cause against the proposed penalty of dismissal. Thereafter the Divisional Manager by his order dated 21-5-85 dismissed the concerned workman from services although he was not competent to pass any such order against the concerned workman, he being lower in rank to the officer who had appointed the concerned workman. The concerned workman preferred an appeal before the Zonal Manager, Calcutta and thereafter he submitted a memorial to the Chairman of the corporation but the same was rejected. Thereafter the concerned workman raised an industrial dispute and submitted a demand before the management to recall the order of dismissal passed against him and to reinstate him. But the management did not accept the demand of the concerned

workman. Thereafter the conciliation proceedings were held by the ALC(C), Patna which ended in failure and thereafter on receipt of the failure report, the Central Govt. referred the present dispute for adjudication to this Tribunal. It is submitted by the workmen that the order of dismissal passed against him was bad in law and on facts.

It was submitted on behalf of the management that as the concerned workman was dismissed from service after holding a domestic enquiry into the charges against him the fairness or otherwise of the domestic enquiry be first decided as a preliminary issue so that in case it is held that the enquiry was not fair and proper the management may have a chance to adduce fresh evidence before the Tribunal to establish the charges against the concerned workman. It also appeared from the W.S. of the concerned workman that the fairness and propriety of the enquiry proceeding was being challenged. Accordingly fairness or otherwise of the domestic enquiry was taken up first for hearing and the same was decided by this Court vide order dated 22-5-1986 holding that the domestic enquiry into the charges against the concerned workman was fair and proper. Thereafter the case was set for hearing on merit.

The points to be decided in this case are (1) whether the management was justified in dismissing the concerned workman on the charges levelled against him and it has to be seen whether the order of the management could be justified on the materials in the domestic enquiry (2) whether the decision of the National Industrial Tribunal would operate as resjudicata in respect of the charge dated 25-2-75, (3) whether the Divisional Manager, Muzaffarpur was competent to pass the order of dismissal against the concerned workman.

I will first take up the point whether the decision of the National Industrial Tribunal would operate as resjudicata in respect of charge dated 25-2-76. The photo copy Case No. NII(B)6 of 1973 has been filed in this case. It shows that the Central Govt. National Industrial Tribunal, Jabalpur Presided over by Shri Justice S. N. Katju had decided the application under Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act, 1947 in which the Divisional Manager, LIC Muzaffarpur was the applicant and the concerned workman Shri R. P. Yadav was the Opp. Party. Shri R. P. Yadav was dismissed from the services of the corporation by the Divisional Manager under regulation 39(1)(g) of the Staff Regulation 1960 with effect from 18-3-75. He had been chargesheeted by the Divisional Manager on 20-4-71 and the photocopy of the said charge is Ext. M-1 in this case. It was alleged in the said chargesheet that the concerned workman had applied for the revival of his lapsed policy No. 1010258658 and in the declaration of health in Form No. 460 dated 22-9-69 had applied to Question No. 5 as stated in the said chargesheet. It was further alleged that out of the aforesaid deposits the premium due with interest thereof amounting to Rs. 3298 were to be adjusted but in fact out of the aforesaid deposit only Rs. 25 had been deposited by the concerned workman and all other deposits pertained to other policy holders and as such the concerned workman was charged of making false statement. It was also alleged that when sundry receipt for the revival of the said policy was prepared by P.H.S. department on the basis of his application and declaration of health in Form No. 460 for revival of his policy and was sent to to the accounts department for verification, the Opp. Party put his initials on the sundry receipts in token of having checked correctness of the deposit made by him. The Dealing Asst. failed to point out that all other deposits except for Rs. 25 did not pertain to the policy of the concerned workman. He was also charged for having made entries in the deposit adjustment book for branch of Hazipur sub Office for adjustment of these deposits to the credit of his own policy and thus the concerned workman by suppression of facts got his policy fraudulently revived. The present charge Ext. M-1 dated 25-2-75 is almost the same charge as contained in Ext. M-1 for which the concerned workman had initially been dismissed by the management. Since the adjudication proceeding was pending at that time before the National Industrial Tribunal, Jabalpur an application was filed by the corporation before the said Tribunal under Section

33(2)(b) of the I.D. Act for approval of the dismissal of the concerned workman. It is clear therefore that the order of the National Industrial Tribunal Jabalpur dt. 21-12-74 was passed in an application under section 33(2)(b) of the I.D. Act. It has been submitted on behalf of the concerned workman that as there is already a decision of the National Industrial, Jabalpur under Section 33(2)(b) of the I.D. Act, in respect of charge Ext. M-1 it was almost the same charge as that alleged in Ext. M-2 and as such the concerned workman could not have been again charged for the same allegation when there was already a decision of competent Tribunal in which the order of dismissal passed by the management was not approved by the National Industrial Tribunal. On the contrary the submission made on behalf of the management is that the decision under section 33(2)(b) of the I.D. Act will not in affect act as resjudicata in respect of the charge Ext. M-1[2]. In respect of the contention the management has cited a decision reported in 1980 Vol. II LLJ Page 29. In the said case an employee of the management was dismissed after enquiry and an approval by the Industrial Tribunal under Section 33(2)(b) of the I.D. Act. Thereafter a reference was made for adjudication of the dispute under Section 10 of the I.D. Act. It was held by their Lordships in a proceeding under Section 33(2)(b) of the I.D. Act, the Tribunal may approve of the action of the management against his employee on a prima facie finding that the enquiry held against the employer was proper and legal and that although the principles of natural justice were complied with. The Tribunal is not to decide finally as to the legality and propriety of the enquiry but it comes to a prima facie finding in that regard. As the point cannot be said to have been finally decided by the Tribunal. There is no question of finding of the Tribunal operating as resjudicata in the subsequent proceeding under section 10 of the I.D. Act. Their Lordships also observed that it is well settled that the finding on an issue in order to be a resjudicata in a subsequent proceeding, the issue must have been heard and finally settled. It will thus appear from the judgement that the decision in a proceeding under Section 33(2)(b) action stand as resjudicata in a subsequent proceeding under Section 10 of the I.D. Act.

The scope of Industrial Tribunals jurisdiction in case of approval of action taken on the basis of domestic enquiry is also dealt with in a decision by the High Court Orissa reported in 1976 Vol. I LLJ page 153. In the said case the petitioner who was a workman under Hindustan Steel Ltd, Rourkela was dismissed from service following two enquiries into the certain charges. As the industrial dispute was then pending the management had sought permission of the Tribunal under Section 332(b) of the I.D. Act and it was accorded. Thereafter the said order was challenged. Their Lordship held after considering the case of the Hon'ble Supreme Court regarding the scope power and function of the Tribunal under Section 33(2)(b) of the I.D. Act that the jurisdiction of the Tribunal is limited to the enquiry as to whether a prima facie case has been made out by the employers against the employee or not and the Tribunal under Section 33(2)(b) has not considered the merit of the rival contention as if it was trying the case itself. The Tribunal does not sit in appeal over the finding of the enquiry officer and to re-appreciate the evidence for itself. The Tribunal when it comes to the conclusion that the management has not acted mala fide that there has been proper enquiry and that the conclusion arrived by the enquiry officer is a possible one on the evidence before it the Tribunal cannot substitute its own judgement for that of the enquiry officer through it may have come a different conclusion on the evidence adduced before the Enquiry Officer. It will appear from the above two decisions the scope of a decision under Section 33(2)(b) of the I.D. Act is limited one where a prima facie finding has to be made under Section 33(2)(b) of the I.D. Act and that as the scope of Section 33(2)(b) is limited it cannot stand as resjudicata and the same dispute may again be raised under Section 10 of the I.D. Act. I hold therefore that the decision made by the National Industrial Tribunal Jabalpur in the application under Section 33(2)(b) of the I.D. Act will not stand as resjudicata so as to preclude the management from holding a domestic enquiry into the charges

against the concerned workman in respect of which formerly chargesheet had been submitted and domestic enquiry had been held.

Now let us see whether the management was able to establish the charge incorporated in Ext. M-1/2 dated 25-2-75. The charge in Ext. M-1/2 is in two parts. The first part is that the concerned workman had applied for revival of his lapsed policy No. 1058658 and that he gave details of deposits in answer to question No. 5 of Form No. 460 totalling Rs. 3298/- out of which only 25 belonged to the concerned workman and all other amount pertained to other different policy holders as detailed in the chargesheet and as such the concerned workman is alleged to have made false statement. The second part of the charge in Ext. M-1/2 is that the concerned workman on the basis of application and personal statement regarding health in Form No. 460 in respect of his policy got the adjustment voucher and Sundry receipts No. 4898 prepared for revival of his policy and that when the adjustment voucher and Sundry receipt were sent by P.H.S. department to accounts department for verification and adjustment of deposits. The concerned workman being the dealing assistant in the accounts department put his initial on the Sundry receipt in token of his having checked the correctness of the deposit and failed to point out that all other deposits except for Rs. 25 did not belong to his policy and that he also made an entries in deposits adjustment book for Hazipur Sub-office for adjustment of these deposits to his own credit and in the process he first wrote in his book DOC No. 90824 against the deposit of Rs. 530/- and subsequently changed it D.O.C. No. 806 which also did not belong to the concerned workman's policy. D.O.C. No. 806 dated 3-8-68 for Rs. 5757.33 P. pertained to policy No. 31729816 and 31729820 on the life of Shri A.K. Choudhary and thus the concerned workman suppressed the facts manipulated records and got his policy fraudulently revived. It is alleged that the concerned workman knowingly acted in a manner highly detrimental to the interest of the corporation.

The management examined three witnesses in all before the Enquiry Officer to substantiate the charges levelled in Ext. M-1/2 they were 1. Shri S.S. Jha, (2) Kedar Mishra and (3) Shri N. N. Singh. It will appear from the evidence of witness No. 3 Shri M.N. Singh examined before the Enquiry Officer that B.O.C. No. 90824 dated 3-8-68 belonged to Smt. R.S. Devi under Policy No. 10226975 Ext. 66 marked before the Enquiry Officer supports what Shri M.N. Singh stated about. It will appear from the evidence of witness No. 2 Kedar Mishra and deposit Cash Book Ext. 45 at page 26 dated 13-9-68 that Rs. 800/- deposited under D.O.C. No. 1151 dated 13-9-68 pertained to the policy No. 70749854 which was received from Gauhati LIC Officer. The witness No. 2 further stated that there was no D.O.C. No. 1151 dated 5-9-68 as stated by the concerned workman in his personal statement as the entries in D.O. deposit cash book started from D.O.C. No. 1010 and ended with D.O.C. No. 1017 and this fact is amply made clear from Ext. 46. He also stated that the amount of Rs. 800/- under D.O.C. 1151 dated 13-9-68 did not pertain to the policy of the concerned workman. It will appear from D.O. deposit cash Book Ext. 48 at page 9 dated 21-8-69 that Rs. 1000 deposited under D.O.C. No. 660 dated 21-8-69 pertained to Shri Balaram Singh's policy No. 29433870 and thus this amount also does not pertain to the concerned workman. Shri Kedar Mishra further stated that D.O.C. No. 685 dated 26-8-79 is of Rs. 943.75P. and not Rs. 94300 as stated by the concerned workman in the health Form No 460. Cash Book Ext. 49 at page 13 will show that the amount of Rs. 943.75P. pertains to policy No. 29522183 belonging to Shri C. Singh and as such Shri Kedar Mishra has rightly stated in his evidence that this amount does not pertain to the concerned workman. Witness No. 2 further stated that the said amount of Rs. 943.75 was subsequently transferred to Sitamarhi Branch on 17-9-69 as shown in remarks column of Ext. 49 Shri Kedar Mishra has stated that Rs. 25/- deposited under D.O.C. No. 799 dated 22-9-69 pertains to the concerned workman under his policy No. 10258658. Page 34 of the D.O. deposit cash book dated 22-9-69 marked Ext. 50 shows that Rs. 25 pertains to the concerned workman. The said amount of 25 deposited by the

concerned workman on 22-9-69 was adjusted as per Sundry receipt No. 4898 under the writing of the concerned workman himself who was dealing with the adjustment matter of Hazipur branch office. Ext. 50, 51 and 52 are the relevant entries in this connection. Shri Kedar Mishra identified the initial of the concerned workman on page 34 of Ext. 52 Witness No. 1 M.N. Singh also stated that the adjustment of Rs. 25/- under D.O. No. 789 dated 22-9-69 was made by the concerned workman under his own initial and he also identified the signature of the concerned workman at the right hand bottom corner of Sundry receipt No. 4898. He has also stated that the entries in D.O. deposit adjustment book for branch marked Ext. 53 was made by the concerned workman. It will also appear from the evidence of Shri M.N. Singh that only one deposit of Rs. 25/- was written off and other four items of deposit were leftover. In the adjustment book of branches in Ext. 53 although the adjustment entries had been passed in respect of all five deposits mentioned in personal statement of the concerned workman. Witness No. 1 Shri S. S. Jha, stated before the enquiry officer that he had prepared the revival renewal slip. Ext. 42 on the basis of the particulars given in the personal statement of the concerned workman dated 22-9-69 marked Ext. 41. He had prepared the adjustment voucher Ext. 43 and the Sundry receipts No. 4898 dated 22-9-69 marked Ext. 44. He has stated that the concerned workman had personally requested for the Sundry receipt and adjustment voucher and as such it was given to him for onward transmission to accounts department for checking and making adjustment. According to his evidence it will appear that the deposits are checked in the accounts department and if any discrepancy is detected it is returned to P.H.S. department for making necessary correction. He also stated that the adjustment voucher of Sundry receipt were not returned to the P.H.S. department. According to the evidence of Shri M. N. Singh it will appear that Sundry receipt No. 4893 dated 22-9-69 does not tally with the entry with the adjustment book. It will thus appear from the evidence discussed above that all the amount which were shown in the health Form No. 460 dated 22-9-69 and for which the concerned workman has been chargesheeted vide Ext. M-1/2 did not belong to the concerned workman except the amount of Rs. 25/- which was deposited by him under D.O.C. No. 799 dated 22-9-69. It is clear therefore that the concerned workman had made a false statement in the health Form No. 460 in order to make wrongful gain as he was posted in the accounts department and was dealing with the adjustment matters.

The second charge in Ext. M-1/2 against the concerned workman is that on the basis of the personal statement in Form No. 460 in respect of policy No. 10258658 he got adjustment voucher and Sundry receipt No. 4898 prepared for the revival of his lapsed policy and when the same was sent by P.H.S. department to accounts department for verification and adjustment of deposit, the concerned workman put his initial on the Sundry receipt in token of his having checked the correctness of the deposit being the dealing assistant in the accounts department and thereby he failed to point out that except the deposit for Rs. 25/- other four deposits did not pertain to his policy. It is further alleged that he also made the entries in the deposit adjustment book for Hazipur sub office for adjustment of the deposits to the credit of his own policy. It is alleged that he suppressed the facts, manipulated records and got his policy fraudulently revived. The concerned workman claimed that all the deposits mentioned in the chargesheet dated 25-2-75 were his own. He submitted that pucca receipt had been issued to him after revival of his policy and thereafter he continued to pay the premium upto July, 1970 and as such the fact that the corporation continued to except his premium goes to show that the revival of his policy was correct. It was also alleged that the papers filed on behalf of the disciplinary authority before the Enquiry Officer was forged and not the original one. He also said that the initials alleged to have been put on the Sundry receipt was not his own. It will appear on perusal of the documents produced by the management and alleged to be forged by the concerned workman were written in the normal course of Business and it has not been stated that other entries in this documents were also forged. It cannot therefore be said that only the entries

in respect of the concerned workman in the documents were forged and fabricated and that the other entries were correct. The claim of the concerned workman that all the deposits mentioned in the charge sheets were his own has not at all been explained by him. It is also discussed that except the deposit of Rs. 25 all other deposits were in respect of other policy holders and the concerned workman did not produce any paper to show that the said amount had been deposited by him. He has not produced any receipt to show that he had made those deposits. Had he deposited the said amount he must have receipts and those receipts would have been produced by the concerned workman or he should have pointed out earlier that although he had made the deposits the same was incorrectly shown by the management. The management's witness Shri S. S. Jha has denied that he had checked the deposit particulars as there was no practice. It was the duty of the concerned workman to check the deposit entries given in the Sundry receipts while writing of and asking entries regarding adjustment in the D.O. deposit adjustment book and in case of any item of Sundry receipt not being found in the deposit book should have been returned to the P.H.S. Department for its correction but the concerned workman did not do so. It will thus appear that the concerned workman knowingly acted in a manner prejudicial and detrimental to the interest of the Corporation. The concerned workman had denied his signature on the Sundry receipt but the two management's witness Shri M.N. Singh and K. Mishra working in the accounts department have identified the signature of the concerned workman on the Sundry receipt. It appears that the concerned workman had signed the Sundry receipt in order to show the genuineness and correctness of the entries in the Sundry receipt and adjustment voucher. It will thus appear that the management had established both the charges levelled against the concerned workman in Ext. M-1|2.

The concerned workman was charge sheeted vide Ext. M-1|3 dated 22-4-75. It was alleged in the said charge sheet that the concerned workman took the joint life policy bond No. 10256957 from Shri R. P. Lall the policy holder for getting his age admitted as stated by Shri R.P. Lall in his letter dated 1-2-1971 addressed to the Divisional Manager. But the concerned workman actually managed to obtain the loan of Rs. 2400 on 26-9-68 by depositing the policy bond of R.P. Lall and his wife and papers required in connection with it on behalf of the policy holders. It is further alleged that with a view to make further wrongful gain the concerned workman got prepared the adjustment voucher dated 26-8-70 and Sundry receipt No. 6301 dated 26-8-70 for Rs. 1259.75 P. towards payment of previous loan and interest thereon in respect of the above policy No. 10256957 and that he altered the amount afterwards in the adjustment voucher of Sundry receipt from Rs. 1259.75 to Rs. 2259.75 P. and when those two documents were sent to the accounts department for verification and adjustment for the same, the concerned workman put his signature on the Sundry receipt indicating that he had checked the D.O. deposit cash book and found it correct and this without any deposit under D.O.C. No. 696 dated 26-8-70, the concerned workman adjusted Rs. 2259.75 P. towards payment of loan and interest against the said policy. It is further alleged that on the basis of false and fictitious payment of Rs. 2259.75 P. towards repayment of loan and interest thereon the concerned workman again raised a loan of Rs. 3400 against the above policy and received a check for Rs. 2973.39 P. issued in his favour after deducting the outstanding loan amount of Rs. 426.67 P. from the total loan amount of Rs. 3400 by submitting false papers on the above policy and thus knowingly he acted in a manner highly detrimental to the interest of the Corporation and in a manner highly prejudicial to good conduct.

It was submitted on behalf of the concerned workman that this charge sheet was subject-matter of earlier charge Ext. M-1|1 dated 23-9-72. Admittedly no enquiry was held on the earlier charge sheet dated Ext. M-1|1 and the said charge remained. There is no evidence to show that the said charge was dropped by the management, and as such I think that the management was quite competent to proceed with the said charge.

The management examined 11 witnesses before the enquiry officer in respect of the allegations made against the concerned workman, and the concerned workman examined three defence witnesses. The first charge in respect of Ext. M-1|3 in nutshell is that the concerned workman took the joint policy of R. P. Lall and his wife for getting his age admitted and on its basis first took loan of Rs. 2400 alleging that he has been authorised to take the loan on behalf of R. P. Lall and his wife. In this connection the management witness Shri S. K. Guha, Asstt. working in loan section has stated that he had prepared the loan review slip Ext. 90 on the request of the concerned workman and he also prepared the loan bond of Rs. 2400 which was received by the concerned workman on 24-2-68 on behalf of the policy holder R. P. Lall and his wife and the concerned workman had written his full signature on Ext. 90. Shri Guha also prepared the loan bond on receipt of stamp fee and relative misc. deposit receipt for Rs. 80 and he handed over the same to the concerned workman. Shri Guha had prepared Ext. 92 which was the payment voucher on receipt of the executed loan bond and he had prepared the loan forwarding letter Ext. 94 in favour of the concerned workman in accordance with the advice stated in the loan bond. Shri B. K. Ghosh the then section head of the loan section, also supported Shri Guha in this respect. According to the management witness Shri Sharma the receipt for Rs. 30 marked Ext. 94 bears his signature and the entire writing in Ext. 94 is that of the concerned workman. The policy holders Shri R. P. Lall vide his complaint Ext. 125 dated 12-71 had stated in it that he had given his policy for admission of his age to the concerned workman. Shri R. P. Lall was examined as witness before the Enquiry Officer and stated that he had not taken any loan from his policy No. 10256957 and that the concerned workman did not return back his policy after he had taken it for admission of his age. He has also denied to have deposited any stamp fee for any loan. He has categorically stated that the concerned workman never handed over the amount of loan to him. It is clear therefore that the concerned workman after taking the joint life policy of Shri R. P. Lall and his wife raised loan of Rs. 2400 for himself by depositing the policy bond and other papers and received the said amount on behalf of the policy holders.

The management filed many documents and also examined many witnesses to prove charge No. 2 of charge sheet Ext. M-1|3. The management's witness Shri Kedar Mishra stated that vide D.O.C. No. 696, Rs. 1259.75 was deposited by cheque on 26-8-70 but as there was some defect in the cheque the said amount was not deposited and the receipt was cancelled and entry in the deposit cash book was also penned through. It will thus appear from his evidence that there was no deposit at all in respect of Rs. 1259.75 on 26-8-70. Shri K. Mishra had also stated that the cheque which was tendered at the counter was returned to the depositor after writing in the deposit cash book. He also identified the signature of the concerned workman. Shri N. K. Thakur a witness of the management had stated that Ext. 102 is in the writing of the concerned workman but it bears his initial. He also stated that voucher Ext. 102 and Sundry receipt Ext. 103 were written by the concerned workman and the sundry receipt 103 was received by the concerned workman on behalf of Shri R. P. Lall and the concerned workman had received the same under his signature. It will further appear from the evidence of Shri N. K. Thakur that the amount of Rs. 1259.75 P. under D.O.C. No. 696 was later on changed as Rs. 2259.75 P. by changing the figure '1' of 1259.75 to '2' in the sundry receipt No. 6301 and also in the adjustment voucher. This was detected from Ext. 106 as the concerned workman could not change the copy kept in the office and the said Ext. 106 shows that the amount was Rs. 1259.75 only. The fact that an interpolation was made in D.O.C. 696 is further strengthened by the evidence of Shri N. K. Thakur who has stated that at the time of signing of the adjustment voucher and sundry receipt there was no overwriting or cutting in Ext. 102 and 103. He has stated that Ext. 102 and 103 had been given by him to the concerned work-

man for further action in the accounts section for verification of the amount deposited and that after verifying the adjustment in the accounts department the concerned workman again brought back the sundry receipt Ext. 103 and after affixing the revenue stamp the concerned workman took the same. Both witnesses Shri M. N. Singh and Shri N. K. Thakur identified the signature of the concerned workman on the sundry receipt, Ext. 103. Shri M. N. Singh stated that the initial of the concerned workman indicates that he had checked and verified the deposits of D.O.C. No. 696. He has also stated that there was no overwriting in the deposit adjustment book of the branches in Sl. No. 79 dated 26-8-70 at the time of the signature on Ext. 103 and that the alteration was made by the concerned workman subsequently who was dealing with the matter.

On the third charge of Ext. M-1/3 the management had examined Shri A. K. Sinha. He has stated that the loan review slip had been prepared by the concerned workman except a few column which had been filled up by witness Shri S. K. Guha, Ext. 77 is the loan application on which the concerned workman had furnished the premium position on 28-7-70 and it contains the signature of the concerned workman. Witness Shri G. Sharma stated that he had received the stamp fee of Rs. 42 and the entire receipt Ext. 79 had been filled up by the concerned workman. Witness B. N. Jha stated that he had enquired whether there was any person named Rambilash Singh, M.A.B.L., at Language whose name was stated in the loan bond Ext. 89 for Rs. 3400 when he was asked by the Divisional Manager to enquire about it. On his enquiry he found that there was no person named Rambilash Singh, M.A.B.L., at Language and in its support Ext. 111, 112 and 113 has been produced. Ext. 110 shows that Rambilash Singh had not signed on the loan form Ext. 89. Management witness Shri Guha stated that the loan bond was issued and on receipt of the said loan bond Ext. 89 he had prepared payment voucher in favour of the concerned workman as the concerned workman had been authorised to receive the payment. The policy holder R. P. Lall who had complained vide Ext. 125 stated before the enquiry officer that he had not applied for loan. He had not signed the loan application Ext. 77, he had not deposited the amount of stamp fee, he and his wife had not signed on the executed loan bond Ext. 89 and that he did not receive any amount from the concerned workman. It will thus appear from the evidence of Shri R. P. Lall that the concerned workman took his policy bond for getting first age admitted and fraudulently first raised the loan for Rs. 2400 and thereafter raised loan on the said bond for Rs. 3400. I also hold that charge No. 3 of Ext. M-1/3 has been established.

The three witnesses examined in defence on behalf of the concerned workmen are only for the purpose of showing the relationship between the Shri D. N. Roy, Development Officer at Hazipur Branch with R. P. Lall. They have not given evidence in respect of the allegation made in Ext. M-1/3 as such they are not of much importance. Even if there was any enmity between Shri R. P. Lall and Shri R. P. Yadav the said matter does not affect the truth of the finding that the concerned workman had raised the loan of Rs. 2400 and Rs. 3400 on the basis of the loan bond of Shri R. P. Lall and his wife. The relationship of

Shri R. P. Lall and Shri D. N. Roy do not affect the evidence in the case. In view of the discussion made above I hold that the charges levelled against the concerned workman vide Ext. M-1/3 has been established.

In view of the above discussion I hold that the order of the management in dismissing the concerned workman on the charges levelled against him was justified on the materials in the domestic enquiry.

It has been contended on behalf of the concerned workman that he was appointed by the Zonal Manager, Eastern Zone, Calcutta and as such the Divisional Manager, Muzaffarpur who is an officer of rank lower than the Zonal Manager was not the competent authority to pass the order of dismissal dated 19-5-81. Admittedly the concerned workman was appointed by Zonal Manager, Eastern Zone, Calcutta, in the year 1957 and was posted at Muzaffarpur Divisional Office. It is also admitted that the concerned workman was dismissed from service with effect from 19-5-81 by the Divisional Manager, Muzaffarpur. The present charges Ext. M-1/2 and M-1/3 was framed against the concerned workman on 25-2-75 and 22-4-75 respectively. It is also admitted by the concerned workman in para-5 of his W.S. that the conditions of service including the matter of disciplinary action of an employee of the Corporation are covered by LIC India Staff "Regulations" 1960. We are therefore to look to the LIC India (Staff) Regulation, 1960. Regulation 39 of the (Staff) Regulation deals with penalties which can be imposed by the disciplinary authority specified in schedule 1 against an employee who commits a breach of regulation of the Corporation. In Clause 2 of Regulation 39 it is provided "No order imposing on an employee any of the penalties specified in Clause (b) to (g) of sub-regulation (1) shall be passed by the disciplinary authority specified in the schedule 1 without the charge or charges being communicated to him in writing and without his having been given reasonable opportunity of defending himself against such charges and of showing cause against the action proposed to be taken against him. In clause 3 it is provided that the disciplinary authority empowered to impose any of the penalties under clause (b) to (g) may itself enquire to such of the charges as are not admitted or if it considers necessary he may appoint an enquiry officer for the purpose. Schedule 1 which is mentioned in Regulation 39 deals with the appointment of disciplinary and appellate authorities. The concerned workman was an employee of Class III Category and it shows that his appointing authority, disciplinary authority (for all penalties) is the Divisional Manager and the Appellate authority is Zonal Manager. Admittedly the charge sheets were issued under the signature of the Divisional Manager, Muzaffarpur and the order of dismissal was passed by the Divisional Manager, Muzaffarpur. Thus regulation 39 of the Staff Regulations 1960 appears to have been complied with. Regulation 87 is the repealing clause in the staff regulation which provides that the LIC of India (Staff) Regulations, 1956 are repealed. Thus the staff regulation of 1956 was no longer in existence after the passing of the Staff Regulation 1960. Thus the power of framing the charge taking disciplinary action was with the Divisional Manager who had the authority under the Staff Regulations 1960. Staff Regulation 1960 has the force of law. In a case reported in 1975 Lab. IC-381=1975 Supreme Court 1331 held that the regulation framed under

statute applies uniform terms to everyone or to all members of same group or class. The LIC is required by the statute to frame regulations inter alia for the purpose of the duties and conduct and conditions of service of officers and other employees. Thus regulation impose obligation on the statutory authorities. The statutory authorities cannot deviate from the conditions of service. Any deviation will be enforced by legal sanction of declaration by courts to invalidate actions in violation of rules and regulation. The LIC Act confer power on the corporation to make regulation as to the method of recruitment of employees and the terms and conditions of service of such employees or agents. The regulations are not only binding on the authorities but also on the public. As the LIC can always frame regulations including the power to amend and replace the regulations, the Staff Regulations, 1960 framed by the corporation is binding on the employees. The action taken against the concerned workman by the Divisional Manager, Muzaffarpur is in strict conformity with the provision of the staff regulations in force at the relevant time. As the Staff Regulation, 1956 had been repealed by the Staff

Regulation, 1960 the old regulations was no more in existence at the relevant time and as such even if the concerned workman had been appointed by the Zonal Manager the regulations empowered the Divisional Manager to take disciplinary action and pass the penalties thereon under Regulation 39 of the Staff Regulation, 1960. I hold therefore that the Divisional Manager, Muzaffarpur was competent to pass the order of dismissal against the concerned workman.

In view of the above discussions, I hold that the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Muzaffarpur in dismissing Shri R. P. Yadav, Assistant in the Divisional Office, Muzaffarpur with effect from 19-5-81 is justified and consequently the concerned workman is entitle to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-17012/30/85-D.IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer